कानपुर, मंगलवार, 10 फरवरी, 2026
वर्षः 03, अंकः 40, पृष्ठः 8+4

सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com
Website: www.swarajindianews.com

सांध्यकालीन समाचार पत्र

स्वराज इंडिया

इनसाइड एपस्टीन फाइल्स से यूरोप में सियासी जलजला...>Pg12

आईआईटी कानपुर को मिला गोल्डन जुबली गिफ्ट...>Pg03

मूल्यः 2 ₹

कानपुर देहात की फैक्ट्रियों से फैला जहर का साम्राज्य

- नोन नदी से यमुना तक बह रहा रासायनिक मौत-प्रवाह, माघ मेला जल पर भी संकट
- क्रोमियम कांड के बाद भी नहीं थमा प्रदूषण,रात के अंधेरे में बहाया जा रहा औद्योगिक ज़हर
- खुलासों के बावजूद इकाइयां चालू, किसके संरक्षण में फल-फूल रहा 'मौत का कारोबार'?

जहर की यात्रा...
- रनिया औद्योगिक क्षेत्र
- खानचंद्रपुर-पालनपुरवा के भूजल में क्रोमियम की पुष्टि
- जांच में 103 ग्रामीणों के रक्त में ज़हरीली धातु पाई गई

✍ कानपुर देहात (माती) स्वराज इंडिया न्यूज

कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्रों में फैलता रासायनिक प्रदूषण अब महज़ पर्यावरणीय समस्या नहीं, बल्कि एक धीमी लेकिन भयावह जनस्वास्थ्य आपदा बन चुका है। रनिया औद्योगिक क्षेत्र से लेकर नवीपुर इंडस्ट्रियल एरिया तक फैक्ट्रियों से निकल रहा जहरीला अपशिष्ट नदियों, भूजल, खेती और मानव शरीर को लगातार विषाक्त कर रहा है। हैरानी और चिंता की बात यह है कि बार-बार खबरें, जांच रिपोर्ट और भयावह खुलासे सामने आने के बावजूद प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों पर कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं हो सकी है। इससे प्रशासनिक उदासीनता के साथ-साथ संरक्षण की आशंका और गहरी हो गई है। रनिया औद्योगिक क्षेत्र के खानचंद्रपुर व आसपास के गांवों में भूजल में क्रोमियम जैसी घातक भारी धातुओं की पुष्टि पहले ही हो चुकी है। पालनपुरवा गांव में 103 ग्रामीणों के रक्त में क्रोमियम पाए जाने की रिपोर्ट ने प्रदेश-स्तर पर सनसनी मचाई थी। बावजूद इसके, न तो जिम्मेदार इकाइयों पर ताले लगे और न ही प्रदूषण की जड़ पर प्रहार हुआ। हालात सुधरने के बजाय और ज्यादा खतरनाक होते चले गए।

नवीपुर से नोन नदी, फिर यमुना तक गया विष

नवीपुर औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाला रासायनिक नाला हिम्मापुरवा गांव से होकर गड़ा बाबा मंदिर के पीछे से सीधे द्वितीय नोन नदी में गिराया जा रहा है। यही जहरीला पानी मोहाना, पतरा और कौसम गांवों के पास ठहरते हुए धीरे-धीरे यमुना नदी में समाहित हो जाता है। पर्यावरण विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यही यमुना जल आगे चलकर प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र तक पहुंचता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु स्नान करते हैं। सवाल साफ है–क्या प्रयागराज का जल भी रासायनिक खतरे की चपेट में है?

गांवों में बीमारी, हैंडपंप जहरीला पानी उगल रहे

स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक नाले का पानी इतना जहरीला है कि उसकी दुर्गंध से नशे जैसा असर होता है। पशुओं के लिए यह पानी प्राणघातक बन चुका है। कौसम गांव में अधिकांश हैंडपंपों का पानी पूरी तरह खराब हो गया है। पेयजल संकट के बीच गांव में त्वचा रोग, पेट की बीमारियां, सांस की तकलीफ, आंखों में जलन और अन्य गंभीर रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। ग्रामीण मोजी लाल, राजेश, राकेश, राम करन, नन्दी, हरदेव, आलोक, सुमित सिंह, विवेक, रजनू और शिवम गुप्ता का कहना है फैक्ट्रियों के जमाने से यह गंदा पानी बह रहा है। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, जमीन की उपज खत्म हो गई है। अगर हमारे खून की जांच हो जाए, तो उसमें भी ज़हर जरूर मिलेगा। हम रोज़ बीमार पड़ रहे हैं।

क्या मांग रहे हैं ग्रामीण

- दोषी औद्योगिक इकाइयों की तत्काल बंदी
- उच्चस्तरीय स्वतंत्र वैज्ञानिक जांच
- नदी और भूजल की टेस्ट रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए
- प्रभावित गांवों में शुद्ध पेयजल की स्थायी व्यवस्था
- कौसम गांव सहित अन्य क्षेत्रों में ग्रामीणों की रक्त जांच

यह भी जानना जरूरी

- रात के अंधेरे में छोड़ा जा रहा रासायनिक कचरा
- दुर्गंध से नशे जैसा प्रभाव
- हैंडपंपों का पानी पूरी तरह अनुपयोगी
- त्वचा, पेट, सांस, आंखों की बीमारियों में उछाल
- कृषि भूमि की उपज खत्म
- पशुओं की असमय मौतें
- **पालनपुरवाः** 103 ग्रामीणों के रक्त में क्रोमियम
- **रनिया क्षेत्रः** भूजल स्थायी रूप से दूषित
- अब कौसम व आसपास के गांव उसी राह पर
- अब तक कोई बड़ी फैक्ट्री सील नहीं
- जब खून में ज़हर मिल चुका, तब कार्रवाई क्यों नहीं?
- प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्टें फाइलों में क्यों दफन?

नियम कागजों में, विषाक्त पानी नदियों में

शासन स्तर से स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी औद्योगिक इकाई यदि गंदा पानी नदी या जलस्रोत में छोड़े तो तत्काल बंदी और कठोर कार्रवाई की जाए। इसके बावजूद रात के अंधेरे में रासायनिक अपशिष्ट छोड़े जाने का खेल बेरोकटोक जारी है। यह स्थिति प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला प्रशासन और निगरानी तंत्र की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब रनिया और नवीपुर के प्रदूषण मामले बार-बार मीडिया में उजागर हो चुके हैं, तो दोषी इकाइयों पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या औद्योगिक ज़हर फैलाने वाली फैक्ट्रियों को राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है?

यह है हालात

मोहाना - पतरा - कौसम गांव
- हैंडपंप ज़हरीले
- फसलें नष्ट, पशुधन मर रहा

यमुना नदी
- करोड़ों लोगों के जल स्रोत पर असर
- प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र (संभावित खतरा)
- श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य पर जैव-रासायनिक संकट

नवीपुर इंडस्ट्रियल एरिया
- फैक्ट्रियों से रासायनिक नाला
- बिना ट्रीटमेंट छोड़ा जा रहा अपशिष्ट

हिम्मापुरवा - गड़ा बाबा मंदिर मार्ग
- रिहायशी इलाकों के बीच बहता ज़हर

द्वितीय नोन नदी
- स्थायी प्रदूषण
- जलीय जीवन समाप्ति की कगार पर

प्रताड़ना

एचडीएफसी बैंक पनकी विवाद..

पूर्व महिला कर्मचारी के आरोपों से बैंक प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल

मैं ठाकुर हूं बोलने वाली आस्था सिंह ने भी अपना पक्ष रखा है

» महिला कर्मचारियों की सुरक्षा, निष्पक्षता और आंतरिक शिकायत तंत्र पर उठे गंभीर प्रश्न

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। पनकी स्थित एचडीएफसी बैंक शाखा में वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक बड़े प्रशासनिक और सामाजिक मुद्दे का रूप ले चुका है। वायरल वीडियो के बाद सामने आए आरोपों ने बैंक प्रबंधन की कार्यप्रणाली, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और निष्पक्ष व्यवहार को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।इस पूरे प्रकरण में पूर्व महिला कर्मचारी रीतू मिश्रा ने बैंक स्टाफ पर मानसिक प्रताड़ना, पक्षपात और अभद्र व्यवहार जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। रीतू मिश्रा का कहना है कि बैंक में कार्यरत रहते हुए उनके साथ लगातार भेदभाव किया गया और एक खास महिला कर्मचारी को संरक्षण देकर उनके खिलाफ माहौल बनाया गया।

आस्था सिंह

रिजाइन के दौरान अपमान और मानसिक दबाव का आरोप

रीतू मिश्रा के अनुसार, जब उन्होंने नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया, तब एक मामूली बात को लेकर उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। आरोप है कि बैंक के कुछ कर्मचारियों ने न केवल उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि इससे पहले भी बैंक के कुछ पुरुष कर्मचारियों द्वारा उनके साथ अशोभनीय व्यवहार किया गया था।

श्रम नियमों के उल्लंघन का भी दावा

पीड़िता का कहना है कि नौकरी के दौरान उनसे देर रात तक काम कराया जाता था, जो श्रम कानूनों के स्पष्ट उल्लंघन की श्रेणी में आता है। विरोध करने पर उन्हें नौकरी जाने और बदनामी का डर दिखाकर चुप कराया गया।

इसी भय के चलते वह लंबे समय तक चुप रहीं। वायरल वीडियो में दिखी महिला कर्मचारी पर भी गंभीर आरोप हैं.

विवाद से जुड़े वायरल वीडियो में दिख रही महिला कर्मचारी आस्था सिंह पर भी आरोप सामने आए हैं।

आरोप है कि उन्होंने अपने सहकर्मी, उसकी नन्द और उसके पति के साथ अभद्र भाषा और टिप्पणी की। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बैंक स्टाफ के व्यवहार को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है।

बैंक प्रबंधन की चुप्पी से उठ रहे सवाल

मामले के तूल पकड़ने के बावजूद अब तक एचडीएफसी बैंक प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बैंक की चुप्पी ने संदेह को और गहरा कर दिया है। जानकारों का मानना है कि यदि लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है, तो यह मामला बैंक की साख और विश्वसनीयता के लिए गंभीर संकट बन सकता है।यह पूरा मामला केवल एक शाखा या एक कर्मचारी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसने बैंकिंग सेक्टर में कार्यरत महिला कर्मचारियों की सुरक्षा, कार्यस्थल पर समान व्यवहार और आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली की वास्तविकता को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बैंक प्रबंधन इस मामले में क्या रुख अपनाता है और क्या निष्पक्ष जांच कर पीड़िता को न्याय मिल पाता है या नहीं।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आंदोलन से कॉलेज का अहंकार झुका

संस्थान में लागू अव्यावहारिक समय-सारिणी, उपस्थिति के नाम पर लगाए जा रहे जुर्माने का भारी विरोध

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। महाराणा प्रताप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स, कानपुर में छात्रों की समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा किए गए लगातार आंदोलन का असर दिखने लगा है। छात्रों के दबाव के बाद कॉलेज प्रशासन को अपने कई कठोर और विवादित निर्णयों में संशोधन करना पड़ा है। प्रशासन ने इस संबंध में एक औपचारिक कार्यालय आदेश जारी कर छात्रों की प्रमुख मांगों को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

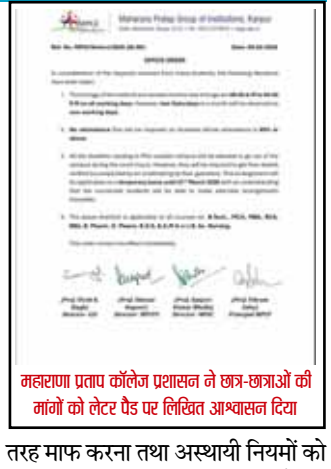

महाराणा प्रताप कॉलेज प्रशासन ने छात्र-छात्राओं की मांगों को लेटर पैड पर लिखित आश्वासन दिया

अभाविप के नेतृत्व में छात्रों ने संस्थान में लागू अव्यावहारिक समय-सारिणी, उपस्थिति के नाम पर लगाए जा रहे जुर्माने, आर्थिक दंड और छात्र हितों की अनदेखी के खिलाफ लगातार आवाज उठाई थी। आंदोलन के बाद जारी आदेश के अनुसार अब संस्थान का समय प्रातः 09:45 बजे से सायं 04:45 बजे तक रहेगा। साथ ही प्रत्येक माह दो शनिवार का अवकाश भी घोषित किया गया है, जिससे छात्रों को बड़ी राहत मिली है।

कॉलेज प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन छात्रों की उपस्थिति 80 प्रतिशत या उससे अधिक होगी, उन पर किसी भी प्रकार का उपस्थिति-आधारित जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। इस निर्णय से छात्रों पर पड़ रहे मानसिक और आर्थिक दबाव में कमी आने की उम्मीद है।इसके अलावा पीजी में रहने वाले छात्रों को लंच समय में परिसर से बाहर जाने की अनुमति भी दी गई है, जिससे उनकी दैनिक आवश्यकताओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा। हालांकि यह व्यवस्था फिलहाल 31 मार्च 2026 तक अस्थायी रूप से लागू की गई है।

अभाविप ने स्पष्ट किया है कि अभी भी छात्रों की कई मांगें लंबित हैं, जिनमें उपस्थिति की अनिवार्यता 80 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत करना, पूर्व में लगाए गए सभी फीस आधारित जुर्मानों को पूरी तरह माफ करना तथा अस्थायी नियमों को स्थायी रूप से लागू करना शामिल है।

इस अवसर पर अभाविप कानपुर प्रांत के प्रान्त मंत्री दिनेश यादव ने कहा कि यह आदेश साबित करता है कि संगठित छात्र शक्ति के सामने प्रशासन को निर्णय बदलने पड़ते हैं। संगठन छात्र हितों के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा और शेष मांगों को लेकर आंदोलन जारी रहेगा।

शारारती तत्वों ने काशी महाकाल एक्सप्रेस पर फेंके पत्थर, यात्रियों में दहशत

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। कानुपर जिले में अज्ञात लोगों ने काशी महाकाल एक्सप्रेस पर कथित रूप से पत्थर फेंके, जिससे प्रथम वातानुकूलित (फर्स्ट एसी) डिब्बे की एक खिड़की के शीशे टूट गए और यात्रियों में दहशत फैल गई। राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने सोमवार को यह जानकारी दी। जीआरपी के अनुसार, यह घटना रविवार रात करीब नौ बजे भीमसेन रेलवे स्टेशन के पास की है जब वाराणसी से इंदौर जा रही यह ट्रेन गोविंदपुरी स्टेशन से रवाना होने के बाद भीमसेन की ओर बढ़ रही थी।जीआरपी थाना प्रभारी हेमंत ने बताया कि पथराव के कारण प्रथम वातानुकूलित डिब्बे की खिड़की का शीशा टूट गया। उन्होंने कहा कि इस घटना में किसी भी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है। बाद में टूटे शीशे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी प्रसारित हुआ। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि रेलवे कर्मचारियों ने शीशे के टुकड़ों को तत्काल साफ कर दिया।थाना प्रभारी ने बताया कि शुरुआती जांच में यह मामला शरारत का प्रतीत होता है और अब तक किसी बड़ी साजिश के संकेत नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि एहतियात के तौर पर इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जांच जारी है। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है ।

आईआईटी कानपुर को मिला गोल्डन जुबली गिफ्ट, 1976 बैच ने दिए 13.40 करोड़

○ इसी बैच ने 25 वर्ष पहले कृत्रिम हृदय शोध प्रोजेक्ट की रखी थी नींव ○ विकास, स्टार्टअप और अत्याधुनिक रिसर्च को मिलेगा बल

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया न्यूज

कानपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर के 1976 बैच के पूर्व छात्रों ने अपने स्वर्ण जयंती मिलन समारोह के अवसर पर संस्थान को 13.40 करोड़ रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा कर एक ऐतिहासिक उदाहरण पेश किया है। यह सहयोग संस्थान में शैक्षणिक अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण, नवाचार आधारित अनुसंधान तथा भविष्य उन्मुख तकनीकी और चिकित्सा परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिया गया है।

गोल्डन जुबली रीयूनियन के दौरान देश और विदेश से आए पूर्व छात्रों ने न केवल अपने छात्र जीवन की स्मृतियां साझा कीं, बल्कि संस्थान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया। कार्यक्रम के दौरान एलुमनाई ने बताया कि आईआईटी कानपुर ने उन्हें वैश्विक स्तर पर पहचान और अवसर प्रदान किए, जिसके प्रति कृतज्ञता स्वरूप वे संस्थान के विकास में भागीदार बनना चाहते हैं।

छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए प्रेरणा

आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मणीन्द्र अग्रवाल ने 1976 बैच के पूर्व छात्रों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि एलुमनाई का यह सहयोग संस्थान की ताकत को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि वर्तमान छात्रों, शोधार्थियों और फैकल्टी के लिए प्रेरणास्रोत भी है। ऐसे योगदान से संस्थान में नवाचार की संस्कृति को और मजबूती मिलती है।

पहले भी निभाई थी ऐतिहासिक भूमिका

बैच के सदस्य मुक्तेश पंत ने जानकारी दी कि 1976 बैच इससे पहले भी संस्थान को सहयोग देता रहा है। लगभग 25 वर्ष पूर्व इसी बैच ने सामूहिक प्रयास से धनराशि एकत्र कर आईआईटी कानपुर में कृत्रिम हृदय आर्टिफिशियल हार्ट शोध परियोजना की शुरुआत कराई थी। यह परियोजना आगे चलकर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुई और कई महत्वपूर्ण शोध कार्यों का आधार बनी।

भविष्य की तकनीक और चिकित्सा शोध को मिलेगा सहारा

संस्थान प्रशासन के अनुसार, इस सहायता राशि का उपयोग नई प्रयोगशालाओं, अनुसंधान सुविधाओं के उन्नयन, स्टार्ट-अप और इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने तथा उभरती तकनीकों और चिकित्सा शोध परियोजनाओं में किया जाएगा। इससे आईआईटी कानपुर को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शोध केंद्र के रूप में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। पूर्व छात्रों ने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में संस्थान के साथ उनका सहयोग जारी रहेगा और वे शिक्षा व शोध के क्षेत्र में आईआईटी कानपुर को वैश्विक मानचित्र पर और ऊंचाई तक ले जाने में भागीदार बनेंगे।

ब्रह्मनगर-ईदगाह मार्ग 25 दिन बाद भी बंद, धंसे डाट नालों में आधा-अधूरा काम

कानपुर। ब्रह्मनगर से ईदगाह को जोड़ने वाला व्यस्त मार्ग डाट नालों के धंसने के 25 दिन बाद भी बंद पड़ा है। हालात ऐसे हैं कि 15 फरवरी तक रास्ता खुलने की संभावना भी कम ही नजर आ रही है। सड़क बंद होने से हजारों लोगों को रोजाना लंबा चक्कर लगाकर आवागमन करना पड़ रहा है।

दो डाट नालों के धंसने से यह मार्ग पूरी तरह बाधित हुआ था। नगर निगम ने सफाई का काम तो कराया, लेकिन मरम्मत और पाइप डालने की रफ्तार बेहद सुस्त बनी हुई है। एक नाले में लोहे का पाइप डालने का काम शुरू जरूर हुआ, मगर अब तक केवल आधा ही पूरा हो सका है। दूसरे नाले पर निर्माण कार्य अभी शुरू भी नहीं हो पाया है। मौजूदा हालात को देखते हुए फरवरी के अंत तक भी मार्ग के पूरी तरह बहाल होने पर संशय बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि काम की धीमी रफ्तार से साफ है कि निगम सिर्फ दावों तक सीमित है, जमीनी स्तर पर तेजी नजर नहीं आ रही।

➪ 15 फरवरी तक खुलने की उम्मीद भी धुंधली, नगर निगम के दावे जमीन पर फेल

> एक डाट नाले में दो पाइप डाले जा रहे हैं, जिनमें से आधा काम पूरा हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि शेष कार्य तेजी से कराया जा रहा है और रास्ता जल्द खोला जाएगा।
> – मीनाक्षी अग्रवाल, प्रभारी अधिशासी अभियंता, जोन-4

- 25 दिन से बंद ब्रह्मनगर-ईदगाह मुख्य मार्ग- दो डाट नालों के धंसने से पूरी तरह ठप यातायात
- एक नाले में आधा पाइप डला, दूसरा अब भी अधूरा
- 15 फरवरी तक खुलने की संभावना कमजोर
- निगम के दावों और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर

उच्च न्यायालय के स्टे के बावजूद नगर निगम ने जारी किए पार्किंग टेंडर, ठेकेदारों में आक्रोश

4 साल से नगर निगम के चक्कर लगा रहे हैं पार्किंग ठेकेदार

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया न्यूज

कानपुर। उच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के स्पष्ट आदेश के बावजूद नगर निगम कानपुर द्वारा पार्किंग ठेकों के नए विज्ञापन प्रसारित किए जाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस मामले में शहर के समस्त पार्किंग ठेकेदारों ने नगर आयुक्त को शिकायती प्रार्थनापत्र सौंपते हुए गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है।

ठेकेदारों का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 में पार्किंग टेंडर की निविदाएं स्वीकृत की गई थीं, लेकिन बाद में नगर निगम की नीतिगत त्रुटियों के कारण टेंडर निरस्त कर दिए गए। उस समय टीन शेड, पानी और शौचालय की व्यवस्था न होने का हवाला देकर ठेके रद्द किए गए थे, जबकि यह कमियां स्वयं नगर निगम की जिम्मेदारी में आती थीं।

ठेकेदारों के अनुसार, इस पूरे प्रकरण में उच्च न्यायालय द्वारा सभी पार्किंग ठेकों को यथास्थिति में बनाए रखने की अनुमति दी गई थी। इसके बावजूद नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रबंधन द्वारा न तो ठेकेदारों को सुचारु रूप से कार्य करने दिया जा रहा है और न ही जमा की गई धनराशि अब तक वापस की गई है। ठेकेदारों का दावा है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की संपूर्ण धनराशि आज तक नगर निगम के पास जमा है।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि यथास्थिति आदेश लागू होने के बाद नए टेंडर विज्ञापित करना न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है। ठेकेदारों ने नगर आयुक्त से मांग की है कि या तो उन्हें कार्य करने दिया जाए, या उनकी जमा धनराशि ब्याज सहित वापस की जाए, अन्यथा वे उच्च न्यायालय में अवमानना की कार्यवाही करने को मजबूर होंगे।

विवादित पार्किंग स्थल

तुलसी उपवन मोतीझील, राजीव वाटिका मोतीझील, चांदनी नर्सिंग होम, नवीन मार्केट के पीछे पीडब्ल्यूडी कार्यालय तक, डफरिन अस्पताल के पीछे, विशाल मेगा मॉल अंबेडकरपुरम कल्याणपुर, बी मार्ट साकेत नगर, जूही गौशाला मॉडल शॉप, मधुराज नर्सिंग होम, कृष्णा टावर सिविल लाइन, एक्सल नर्सिंग होम चुन्नीगंज, कारगिल पार्क मोतीझील, रीजल साइंस सेंटर, आभा नर्सिंग होम, मर्चेंट चैंबर, गैस्ट्रो लीवर सेंटर, प्रेस्ट क्लिनिक, पदम टावर सिविल लाइंस सहित कुल 18 पार्किंग स्थल शामिल हैं।

प्रार्थनापत्र में नगर आयुक्त से यह भी आग्रह किया गया है कि वे उच्च न्यायालय में नियुक्त अधिवक्ता से स्थिति स्पष्ट कर तत्काल उचित कार्यवाही करें।

नगर निगम, कानपुर

निविदा सूचना

... https://etender.up.nic.in ... पूर्व निविदा प्रश्न (PRE-BID QUERIES) ... kanpur_nagarnigam@yahoo.co.in ... पूर्व निविदा बैठक (PRE-BID MEETING) दिनांक 16.02.2026 ...

जोन–1 के सीमान्तर्गत पार्किंग निविदा तिथि– 28.02.2026

निविदा शुल्क	जमानती धनराशि	अंतिम निविदा दिनांक	तकनीकी निविदा दिनांक
रू0 10,000.00+18 प्रतिशत जी.एस.टी. = 11800.00	48,600/-	28.02.2026	28.02.2026

जोन–2 के सीमान्तर्गत पार्किंग निविदा तिथि– 28.02.2026

निविदा शुल्क	जमानती धनराशि	अंतिम निविदा दिनांक	तकनीकी निविदा दिनांक
रू0 10,000.00+18 प्रतिशत जी.एस.टी. = 11800.00	2,51,100/-	28.02.2026	28.02.2026

जोन–3 के सीमान्तर्गत पार्किंग निविदा तिथि– 28.02.2026

निविदा शुल्क	जमानती धनराशि	अंतिम निविदा दिनांक	तकनीकी निविदा दिनांक
रू0 10,000.00+18 प्रतिशत जी.एस.टी. = 11800.00	1,07,800/-	28.02.2026	28.02.2026

जोन–4 के सीमान्तर्गत पार्किंग निविदा तिथि– 28.02.2026

निविदा शुल्क	जमानती धनराशि	अंतिम निविदा दिनांक	तकनीकी निविदा दिनांक
रू0 10,000.00+18 प्रतिशत जी.एस.टी. = 11800.00	3,15,900/-	28.02.2026	28.02.2026

जोन–5 के सीमान्तर्गत पार्किंग निविदा तिथि– 28.02.2026

निविदा शुल्क	जमानती धनराशि	अंतिम निविदा दिनांक	तकनीकी निविदा दिनांक
रू0 10,000.00+18 प्रतिशत जी.एस.टी. = 11800.00	8,26,200/-	28.02.2026	28.02.2026

जोन–6 के सीमान्तर्गत पार्किंग निविदा तिथि– 28.02.2026

निविदा शुल्क	जमानती धनराशि	अंतिम निविदा दिनांक	तकनीकी निविदा दिनांक
रू0 10,000.00+18 प्रतिशत जी.एस.टी. = 11800.00	5,75,00/-	28.02.2026	28.02.2026

अपर नगर आयुक्त — नगर आयुक्त

बिठूर में नवजात की मौत पर बड़ा एक्शन

राजा नर्सिंग होम का पंजीकरण निरस्त अस्पताल के डॉक्टरों पर मुकदमा दर्ज

- बिना अनुमति चल रहा था एनआईसीयू
- 3 दिन में जवाब देने का नोटिस, एनआईसीयू यूनिट सील
- डीएम के निर्देश पर सीएमओ ने की जांच

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

डीएम ने सभी अस्पतालों में जीवन रक्षक उपकरणों की सेफ्टी ऑडिट करने का दिया निर्देश

के समय एनआईसीयू की अनुमति नहीं ली गई थी। इसके बावजूद परिसर में एनआईसीयू चल रहा था। निरीक्षण में अग्निशमन यंत्रों की अवधि समाप्त पाई गई। अनधिकृत एनआईसीयू यूनिट को मौके पर सील कर दिया गया।

कानपुर। बिठूर के ब्रह्मनगर स्थित राजा नर्सिंग होम में वार्मर मशीन में नवजात की जलकर मौत के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर हुई जांच में खुलासा हुआ कि अस्पताल में बिना अनुमति एनआईसीयू संचालित किया जा रहा था।मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरिदत्त नेमी की रिपोर्ट के अनुसार अस्पताल पंजीकृत था, लेकिन पंजीकरण के समय एनआईसीयू की अनुमति नहीं ली गई थी। इसके बावजूद परिसर में एनआईसीयू चल रहा था। निरीक्षण में अग्निशमन यंत्रों की अवधि समाप्त पाई गई। अनधिकृत एनआईसीयू यूनिट को मौके पर सील कर दिया गया।

निरीक्षण के दौरान एक चिकित्सक डॉ. तपो ज्योति आचार्य, दो स्टाफ नर्स प्रदीप गोस्वामी और तनू गौतम तथा एक वार्डब्वॉय अजय उपस्थित मिले।

गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए राजा नर्सिंग होम (पंजीकरण संख्या ऋस्वश्व2122829) का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। अस्पताल को पूरी तरह बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। संचालित पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई होगी। प्रबंधन को तीन कार्यदिवस में स्पष्टीकरण देने का नोटिस जारी किया गया है। साथ ही बिठूर थाना में मृतक नवजात के परिजनों की तहरीर पर राजा नर्सिंग होम के चिकित्सकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) में मुकदमा भी दर्ज किया गया है।

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मरीजों की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। जनपद के सभी अस्पतालों में जीवनरक्षक उपकरणों की अनिवार्य सेफ्टी ऑडिट कराई जाएगी और बिना अनुमति संचालित स्वास्थ्य इकाइयों पर अभियान चलाकर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

आचार्य नरेन्द्र देव नगर निगम महिला महाविद्यालय में भव्य खेल दिवस का आयोजन

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। आचार्य नरेन्द्र देव नगर निगम महिला महाविद्यालय, हर्ष नगर, कानपुर में वार्षिक खेल दिवस का भव्य एवं उत्साहपूर्ण आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं के शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास के साथ-साथ खेल भावना, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता को प्रोत्साहित करना रहा।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्रीरामजी एवं विशिष्ट अतिथि वेणुरंजन भदौरिया के साथ महाविद्यालय की प्राचार्या प्रोफेसर ऋतंगरा द्वारा किया गया।

अतिथियों का पारंपरिक रूप से तिलक, स्मृति चिह्न एवं बैज अलंकरण द्वारा स्वागत किया गया।

मुख्य अतिथि श्रीरामजी ने अपने संबोधन में कहा कि खेलों से अनुशासन, सेवा भाव और राष्ट्र निर्माण की भावना विकसित होती है।

वहीं विशिष्ट अतिथि वेणुरंजन भदौरिया ने शिक्षा, तकनीक, साहित्य और खेलों के समन्वय को समाज के समग्र विकास के लिए आवश्यक बताया। खेल महोत्सव का उद्घाटन गुब्बारे उड़ाकर किया गया।

खेल प्रतियोगिताओं के परिणाम इस प्रकार रहे

- प्लेयर ऑफ द ईयर का सम्मान छात्रा अपर्णा सेठ को दिया गया।
- शतरंज में प्रथम स्थान दीक्षा तिवारी, द्वितीय महक सोनकर और तृतीय प्रियंका बाथम रहीं।
- शॉटपुट में प्रथम चेष्टा तनवानी, द्वितीय वर्षा और तृतीय अपर्णा कश्यप रहीं।
- कैरम में प्रथम पूजा गौतम, द्वितीय शिक्षा सोनवानी और तृतीय मुस्कान गुप्ता रहीं।
- बैडमिंटन छात्रा वर्ग में विजेता रिक्षिता कुरील और उपविजेता तनिध रहीं।
- कबड्डी में विजेता टीम मानविकी और उपविजेता टीम वाणिज्य रही।
- बैडमिंटन शिक्षिका वर्ग में विजेता शिखा मिश्रा और उपविजेता अजिता सिंह रहीं।
- शिक्षणेतर कर्मचारियों की क्रिकेट प्रतियोगिता में विजेता टीम अरुणेश कटियार के नेतृत्व में रही।
- म्यूजिकल चेयर में विजेता मोहित रहे।
- रिले रेस में विजेता टीम घोषित की गई।
- कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर जया भारती एवं डॉक्टर प्रियंका द्वारा किया गया तथा धन्यवाद ज्ञापन क्रीड़ा प्रभारी डॉक्टर प्रियंका सिंह ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। महाविद्यालय की शिक्षिकाओं एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों ने कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता निभाई। खेल दिवस छात्राओं के लिए उत्साह, ऊर्जा और प्रेरणा का सशक्त माध्यम सिद्ध हुआ।

यूपीएस बम्हरौली में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर मलासा विकास खण्ड के यूपीएस बम्हरौली में आज सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाई गई। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को कृमि जनित रोगों से सुरक्षित रखना एवं उनके स्वास्थ्य में सुधार करना है।कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रधानाध्यापक मनोज कुमार मिश्रा, सहायक अध्यापक राजेंद्र गुप्ता,सहित समस्त शिक्षकगण उपस्थित रहे। शिक्षकों की देखरेख में बच्चों को दवा खिलाई गई और कृमि संक्रमण से बचाव के प्रति उन्हें जागरूक किया गया। इस मौके पर विद्यालय के सभी बच्चे उपस्थित रहे और अभियान को सफल बनाने में सहयोग किया। कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न हुआ।

सम्पादकीय

गुमशुदाओं की तलाश और मिलने की आस

पिछले दिनों इस खबर ने दिल्ली और देश के लोगों को चौंकाया कि इस साल जनवरी माह में ही देश की राजधानी में 800 लोग लापता पाए गए, जिसमें महिला, बच्चे व अन्य वयस्क भी शामिल हैं। जैसा कि स्वाभाविक था दिल्ली में लापता लोगों का आंकड़ा सामने आने के बाद आम लोगों में चिंता व्याप्त हो गई। प्रशासनिक स्तर पर भी इस समस्या की ओर अधिकारियों का ध्यान गया। बेलगाम सोशल मीडिया पर तो इन आंकड़ों पर अपनी-अपनी सुविधा और राजनीतिक हितों के मद्देनजर व्याख्या और बयानबाजी सामने आने लगी। पब्लिक फोरम पर कहा जाने लगा कि यह दिल्ली की कानून व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह है। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद घर से निकलने के बाद सुरक्षा इंतजामों को लेकर तमाम तरह की सलाहें दी जाने लगीं। कुछ लोग देश के सिस्टम पर सवाल खड़े करने लगे। कुछ लोगों में भय से जुड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आई। लेकिन इस बाबत दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आंकड़े भी अधिक चिंता बढ़ाने वाले नजर आए। प्रथम दृष्टया यह खबर परेशान करने वाली है, लेकिन पड़ताल में पाया गया कि यह स्थिति पिछले कुछ सालों के आंकड़ों के ही अनुरूप है। अगर हम पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह स्थिति की पुनरावृत्ति ही है। लेकिन यदि बीते कुछ सालों में लापता होने वाले लोगों की संख्या पर नजर डालें तो कहा जाता है कि इस साल जनवरी में सामने आई लापता लोगों की संख्या ज्यादा नहीं है। इस बाबत दिल्ली पुलिस का कहना है कि जनवरी 26 में कुल 1,777 लोगों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्रथम दृष्टया यह संख्या भले ही बढ़ी लगे, लेकिन जब पिछले दो सालों के आंकड़ों से इसकी तुलना की जाती है तो नई तस्वीर उभरती है। दरअसल, इन आंकड़ों की तह में जाएं तो दिल्ली का विशाल इलाका व सघन जनसंख्या घनत्व भी इसके मूल में है।दरअसल, एक बड़ी आबादी रोजगार व अन्य कार्यों के लिए दिल्ली आती-जाती रहती है। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में करीब 24,893 लोग लापता हुए थे। यानी एक माह में औसतन 2,074 लोग। वहीं साल 2025 में ये संख्या 24,508 लोग लापता हुए। अर्थात? हर माह 2,042 लोग गुम हुए। इस दृष्टि से जनवरी, 26 का आंकड़ा इस संख्या से कम है। सवाल है कि 2026 के पहले माह के आंकड़ों को लेकर भय क्यों व्याप्त हुआ? दरअसल, पहले पंद्रह दिनों के आंकड़ों के हिसाब से दिल्ली में हर रोज 54 लोग लापता हो रहे थे। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद लोगों ने इसके मूल में किसी संकट को देखा। दिल्ली पुलिस के अनुसार ये आंकड़े स्थायी गुमशुदगी के नहीं होते।

कुछ लोग अल्पकाल के लिए कहीं चले जाते हैं और देर रात तक घर भी लौट आते हैं। पुलिस का यह भी कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी में ऑनलाइन और ऐप आधारित सिस्टम के जरिये लोग जल्दबाजी में अपने परिजनों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। मसलन यदि कोई बच्चा किसी कारणवश स्कूल से लौटने में देर कर दे, कोई व्यक्ति कुछ घंटों तक फोन संपर्क से कट जाए या कोई बुजुर्ग भटकने पर देर से घर पहुंचे तो लोग गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं।

ये कथित गुमशुदा लोग कुछ समय बाद घर तो लौट आते हैं, लेकिन लोग पुलिस डेटा को अपडेट नहीं करते। फलस्वरूप पुलिस आंकड़ों में उनकी गुमशुदगी बनी रहती है। पुलिस का दावा है कि लापता लोगों को खोजने की दर में लगातार सुधार हो रहा है।

साल 2016 में जो 23,409 लोग लापता हुए थे, उनमें से करीब 85 फीसदी नौ साल के भीतर मिल गए। साल 2025 में दर्ज मामलों में 63 फीसदी लोगों को भी एक साल के भीतर तलाश लिया गया। दलील है कि कई जटिल मामलों में तलाश का काम एक साल तक पूरा नहीं हो पाता। अन्य राज्यों में उनकी तलाश में समय लगता है। फिर भी पुलिस का दावा है कि दिल्ली के लापता लोगों की संख्या का आंकड़ा दुनिया के कई विकसित देशों से बेहतर स्थिति में है।पिछले कुछ सालों के आंकड़ों के ही अनुरूप है। अगर हम पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह स्थिति की पुनरावृत्ति ही है।

समतामूलक समाज लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त

यशवंत सचदेव

समतामूलक समाज लोकतंत्र की अनिवार्य शर्तकानून का स्वरूप प्राकृतिक न्याय वाला होना चाहिए। उसे जाति, लिंग, धर्म के आधार पर न्याय नहीं करना चाहिए। लेकिन सरकारें चूंकि वोट के बहुसंख्यक वाद से चलती हैं, इसलिए हर नीति और कानून वह बनाती हैं, जिससे उन्हें अधिक..कानून का स्वरूप प्राकृतिक न्याय वाला होना चाहिए। उसे जाति, लिंग, धर्म के आधार पर न्याय नहीं करना चाहिए। लेकिन सरकारें चूंकि वोट के बहुसंख्यक वाद से चलती हैं, इसलिए हर नीति और कानून वह बनाती हैं, जिससे उन्हें अधिक से अधिक वोट मिलें।यूजीसी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बारे में ऑनलाइन न जाने कितना कुछ पढ़ा, कितने वीडियो और रील्स देख चुकी। सब लोग अपनी-अपनी तरह से बातें कह रहे हैं।

बचपन से घर में सुनती आई हूं कि जातिवाद बहुत खराब चीज है। इससे हर हालत में मुक्ति पाई जानी चाहिए। ऐसे बहुत से बच्चों को अपने ही घर में पढ़ते-लिखते देखा, अच्छी नौकरियों पर जाते देखा है, जिन्हें तथाकथित निचली जाति कहा जाता है। इन्हें यहां तक पहुंचाने में बड़े भाई की बहुत भूमिका थी, क्योंकि वह दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। उस समय जाति तोड़क आंदोलन भी चलते थे, लेकिन आज इनका कहीं नाम भी सुनाई नहीं देता। यद्यपि पढ़े-लिखे तबके में इस बात पर आम सहमति है कि जाति को खत्म होना चाहिए। सभी को समान अवसर और सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन जातिगत विमर्श नहीं चाहते कि जाति खत्म हो। क्योंकि उन्हें लगता है कि इसी के आधार पर वे सरकार की नीतियों में अपनी जगह बना सकते हैं। अधिक से अधिक हिस्सेदारी पा सकते हैं।नब्बे के दशक में जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई थीं, तब भी ऐसा आंदोलन हुआ था, लेकिन वह बहुत दिनों तक नहीं चला। सामान्य वर्ग ने इसे स्वीकार कर लिया।

तब देश ने भूमंडलीकरण की तरफ अपने कदम बढ़ाए। तमाम बड़ी कम्पनियां आईं। जिन लोगों के लिए सरकारी नौकरियां नहीं थीं, वे उधर चले गए और अवसरों की जो कमी कही जा रही थी, वह उतनी नहीं रही। बड़ी संख्या में लोग विदेश चले गए। बताया जाता है कि भारतीय सबसे अधिक पैसा अपने देश में भेजते हैं। देश की आर्थिकी को बढ़ाने में विदेशों में रहने वाले इन भारतीयों का बड़ा योगदान है, जिसका सेहरा अधिकांश राजनेता अपने सिर बांधते हैं।

एक तरफ तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण लाखों की नौकरियां जा चुकीं या जाने वाली हैं। अब नौकरी जाने का आधार यह भी नहीं रहा कि आप कितने मेहनती हैं। किसी कम्पनी की ग्रोथ में आपका कितना योगदान रहा। कम्पनियों को बढ़ाने में आपने चौबीस सात के हिसाब से काम किया। बल्कि रोबोट ही लाटरी के आधार पर फैसला कर रहे हैं कि किसे रखना है, किसे निकालना है। एआई के जन्मदाता ज्योफ्री हिंटन बार-बार कह रहे हैं कि इससे नब्बे प्रतिशत नौकरियां चली जाएंगी। दुनिया की किसी सरकार के पास बेरोजगारों की इतनी बड़ी फौज से निपटने की कोई योजना नहीं है।टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने ही कुछ दिन पहले कहा था कि बीस साल बाद लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। लोग सिर्फ शौकिया ही काम करेंगे। ऐसे में यदि विकास के लिए आप पुराने औजारों को ही धार दे रहे हैं तो वे नहीं चलने वाले।अपने देश में नौकरियों में लगातार आरक्षणवाद का बढ़ना लोगों को शंकित करता है। लोग खुद कितनी भी तकलीफ झेल लें, लेकिन यदि उनके बच्चों पर कोई बात आती है तो वे इसे नहीं सह सकते। यूजीसी गाइडलाइंस ने यही किया। लोगों को लगा कि अब तक तो नौकरियों पर ही खतरे थे, अब उनके बच्चे पढ़ भी नहीं सकते। वैसे भी दशकों से सामान्य वर्ग कहे जाने वाले लोगों के लिए सरकारों के पास कोई योजना नहीं है। दस प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण से भी कितने लोगों को नौकरियां मिली हैं। भारत सरकार की ही रिपोर्ट कहती है कि सामान्य वर्ग कहे जाने वाले लोगों में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है। लेकिन अपनी ही रिपोर्ट से शायद सरकारों ने आंखें मूंद रखी हैं।जिस लोकतंत्र की दुहाई हम हर रोज देते हैं, वह दरअसल संख्या का खेल है, जिसका जितना वोट, उसे पाने के लिए उतनी ही सरकारी योजनाएं। जितनी जिसकी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी। किसी विदेशी विद्वान ने कहा था कि लोकतंत्र एक सतत युद्ध है, जो दिखाई भी देता है।आम शहरी मध्यवर्ग ने सरकार के नारे कि हम दो हमारे दो को अपना लिया। आज तो यह और बढ़कर, हम दो हमारा एक हो गया है। ऐसे में सामान्य वर्ग की आबादी कम भी होती गई है। बढ़ता शहरीकरण भी इसका एक कारण है। कई वीडियो और रील्स ऐसी देखीं, जिसमें लोग यही कह रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी हमारी ही क्यों है। हम ही टैक्स दें।

सना ए. ताका इची को प्रचंड जनादेश और विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया

चुनाव के परिणाम

डा0 सुधीर कुमार

इस चुनाव को राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने इसलिए भी महत्वपूर्ण बताया क्योंकि प्रधानमंत्री ताका इची ने महज कुछ ही महीनों पहले सत्ता संभाली थी और यह उनका पहला आम चुनाव था। उन्होंने तीन महीने पहले ही निचले सदन को भंग कर दिया था ताकि जनता से स्पष्ट जनादेश लिया जा सके।जापान में निचले सदन के चुनाव परिणाम ने देश की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। इस चुनाव में प्रधानमंत्री सना ए. ताका इची के नेतृत्व वाली लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने अभूतपूर्व जीत हासिल की है। पहले चरण के मतगणना के परिणामों के अनुसार ताका इची की पार्टी अकेले ही निचले सदन में 316 सीटें जीतने में सफल रही तथा उसने गठबंधन सहयोगी के साथ मिलकर कुल 352 से अधिक सीटों का दो-तिहाई बहुमत हासिल कर लिया।

इस प्रकार वह अकेले ही अपनी पार्टी के बहुमत से कहीं आगे निकल गईं और भारी पराजय का सामना करना पड़ा।इस चुनाव को राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने इसलिए भी महत्वपूर्ण बताया क्योंकि प्रधानमंत्री ताका इची ने महज कुछ ही महीनों पहले सत्ता संभाली थी और यह उनका पहला आम चुनाव था। उन्होंने तीन महीने पहले ही निचले सदन को भंग कर दिया था ताकि जनता से स्पष्ट जनादेश लिया जा सके। चुनाव के दिन भी देश के कई हिस्सों में जोरदार बर्फबारी और ठंडे मौसम के कारण मतदान केन्द्रों पर कठिन परिस्थितियाँ पैदा हुईं, लेकिन इसके बावजूद मतदाताओं की भागीदारी अपेक्षाकृत मजबूत रही। यह दर्शाता है कि जापानी जनता ने ठंडे मौसम और मुश्किल हालात के बावजूद महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसले में भाग लेने की प्रतिबद्धता दिखाई।इस चुनाव में विपक्षी दलों को जिस प्रकार की पराजय मिली, वह जापानी राजनीति के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा घटनाक्रम था। मुख्य विपक्षी गठबंधन और छोटे दलों ने जिस तरह अपनी सीटें गंवाईं, उससे स्पष्ट होता है कि इस समय जनता ने ताका इची के नेतृत्व को अधिक भरोसेमंद और स्थिर विकल्प के रूप में चुना। अधिकांश विश्लेषकों का मानना है कि मतदान के पीछे मुख्य कारण आर्थिक और सामाजिक मुद्दों के साथ सुरक्षा नीतियों

पर मतदाताओं की चिंताएँ थीं, जिनके प्रति उन्होंने ताका इची की स्पष्ट सोच को प्राथमिकता दी।ताका इची की जीत का विश्लेषण करते हुए कहा जा सकता है कि यह सिर्फ संख्या की जीत नहीं है, बल्कि यह एक राजनैतिक विश्वास का जनादेश भी है। जापान पिछले कुछ वर्षों से बढ़ते आर्थिक दबाव, बुजुर्ग आबादी से जुड़ी सामाजिक चुनौतियों और बढ़ते क्षेत्रीय तनावों के बीच अपना रास्ता ढूंढ़ रहा है। चीन के साथ संबंधों में तनाव, ताइवान को लेकर बदलती भू-राजनीति तथा अमेरिका के साथ सुरक्षा साझेदारी जैसी विषयों को लेकर जनता के भीतर मजबूत भावनाएँ हैं। ताका इची ने चुनाव के दौरान स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया था कि जापान को न केवल आर्थिक सुधारों की आवश्यकता है बल्कि उसे अपनी रक्षा और वैश्विक भूमिका को भी मजबूती से परिभाषित करना होगा।हम आपको बता दें कि सना ताका इची स्वयं एक लंबा राजनीतिक अनुभव लिये हुए हैं। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा 1990 के दशक में संसद सदस्य के रूप में शुरू की थी और समय-समय पर कई महत्वपूर्ण विभागों तथा मंत्रालयों में काम किया। अपने अनुभव, दृढ़ नीतियों और स्पष्ट विचारधारा के कारण उन्हें पार्टी में एक मजबूत छवि मिली। वह इस चुनाव से पहले जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं और इस जीत ने उन्हें अपनी पार्टी तथा जनता दोनों से मजबूत समर्थन दिलाया है। ताका इची ने अपने राजनीतिक कॅरियर में व्यापक विषयों पर सार्वजनिक रूप से अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है, जिनमें आर्थिक नीतियाँ, सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा जापान की अंतरराष्ट्रीय भूमिका शामिल हैं।उनके नेतृत्व में पार्टी की जीत का एक प्रमुख कारण यह भी बताया जा रहा है कि उन्होंने आर्थिक स्थिरता, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को चुनाव में प्रमुख मुद्दों के रूप में उठाया। जापान की अर्थव्यवस्था बड़े कर्ज़, कम उत्पादन वृद्धि और बढ़ते जीवनयापन लागत जैसी समस्याओं का सामना कर रही थी, जिनके समाधान के लिये जनता अधिक ठोस नीतियों की उम्मीद कर रही थी। ताका इची ने यह विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार इन समस्याओं के समाधान के लिये गंभीर प्रयास करेगी और एक दीर्घकालिक आर्थिक सुधार योजना लागू करेगी।सुरक्षा मामलों में उनकी विचारधारा और भी अधिक स्पष्ट रही है। उन्होंने बार-बार यह कहा कि जापान को अपनी रक्षा नीतियों को अधिक आत्मविश्वास तथा स्वतंत्रता के साथ परिभाषित करना चाहिए। अमेरिका के साथ रक्षा साझेदारियों को और मजबूती प्रदान करना, क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना तथा चीन और उत्तर कोरिया जैसे पड़ोसी देशों से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करना उनकी प्राथमिकता रही है। इस दृष्टिकोण ने उन मतदाताओं को प्रभावित किया जो जापान की क्षेत्रीय स्थिति को एक जटिल तथा बढ़ती चुनौतियों वाला क्षेत्र मानते हैं।

वैश्विक स्तर पर भी इस चुनाव के परिणाम का प्रभाव देखा जा रहा है।

इंडो-पैसेफिक क्षेत्र में जापान की भूमिका महत्वपूर्ण है और ताका इची की जीत ने यह संकेत दिया है कि जापान

घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ, मौके पर ही ठीक होगी वोटर लिस्ट

मतदाता सूची की तार्किक विसंगतियों के निस्तारण को लेकर विशेष प्रशिक्षण

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में पाई जा रही तार्किक विसंगतियों (लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी) के त्वरित निस्तारण के लिए समस्त बूथ लेवल ऑफिसरों (बीएलओ) एवं सुपरवाइजरों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य निर्वाचन आयोग द्वारा चिन्हित विसंगतियों का पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना रहा।

प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत बीएलओ स्वयं घर-घर जाकर संबंधित मतदाताओं को नोटिस देंगे। नोटिस मिलने के बाद मतदाता अपने आवश्यक दस्तावेज बीएलओ को सौंपेंगे, जिन्हें बीएलओ मौके पर ही बीएलओ एप के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड करेंगे।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया के लागू होने के बाद मतदाताओं को तहसील, ब्लॉक या किसी अन्य कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दस्तावेज और फोटो अपलोड होते ही प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी, जिससे आम मतदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी।

निर्वाचन आयोग के सॉफ्टवेयर के माध्यम से मतदाता सूची में पांच प्रकार की तार्किक विसंगतियां चिन्हित की गई हैं। इन मतदाताओं की मैपिंग वर्ष 2003 की मतदाता सूची से की गई है, हालांकि कई मामलों में संदेह की स्थिति सामने आई है। आयोग ने यह सरल प्रक्रिया इसलिए लागू की है ताकि बिना किसी असुविधा के मतदाता सूची को शुद्ध किया जा सके और किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से हटने न पाए।

लापरवाह लेखपालों से एसडीएम नाराज

एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) कार्य में लगाए गए कुछ लेखपालों द्वारा कार्य को गंभीरता से न लेने पर एसडीएम ने नाराज़गी जताई है। सूत्रों के अनुसार जिन लेखपालों की शिकायतें सामने आई हैं, उनमें अधिकांश चौबेपुर ब्लॉक क्षेत्र से जुड़े हैं। आरोप है कि कुछ लेखपाल क्षेत्र में जाने के बजाय तहसील में बैठकर औपचारिकताएं निभा रहे हैं, जिससे कार्य की प्रगति प्रभावित हो रही है। सूत्रों का कहना है कि इस लापरवाही को लेकर जल्द ही संबंधित लेखपालों पर कार्रवाई हो सकती है।

अधिकारियों ने किया जागरूक

चौबेपुर में तहसीलदार अनुभव चंद्रा तथा बिल्हौर में उप जिलाधिकारी संजीव दीक्षित ने बैठक कर बीएलओ और सुपरवाइजरों को पूरी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही मतदाताओं को जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि मतदाता सूची का सही और अद्यतन होना निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव की बुनियाद है, इसी उद्देश्य से यह प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

फिर चर्चा में 'महिला प्रेमी लेखपाल'

सूत्रों के मुताबिक नाराज़गी की सूची में वह लेखपाल भी शामिल है, जो पहले भी अपने व्यवहार और निजी कारणों को लेकर सुर्खियों में रहा है। तहसील में 'महिला प्रेमी लेखपाल' के नाम से चर्चित यह कर्मचारी पूर्व में भी उच्चाधिकारियों की फटकार झेल चुका है, लेकिन इसके बावजूद कार्यशैली में सुधार नहीं दिख रहा है।

शिव बारात को लेकर बिल्हौर कोतवाली में आयोजकों के साथ मीटिंग

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। महाशिवरात्रि पर्व के मद्देनज़र बिल्हौर में निकलने वाली शिव बारात को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में बिल्हौर कोतवाली परिसर में शिव बारात आयोजन समिति के साथ बैठक की गई, जिसमें आयोजन को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में एसीपी मंजय सिंह तथा प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार ने आयोजन समिति के पदाधिकारियों से बारात के मार्ग, समय निर्धारण और भीड़ प्रबंधन से जुड़ी जानकारी ली। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि धार्मिक आयोजन के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसीपी मंजय सिंह ने कहा कि शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी रहती है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट रहेगी। उन्होंने आयोजकों से अनुशासन बनाए रखने और प्रशासन से लगातार संपर्क में रहने की बात कही। प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार ने बताया कि बारात के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने डीजे संचालन को लेकर नियमों का पालन करने, निर्धारित ध्वनि स्तर से अधिक आवाज न करने और किसी भी आपात स्थिति की जानकारी तुरंत पुलिस को देने के निर्देश दिए।

बैठक में महिला सुरक्षा, पार्किंग व्यवस्था और बारात मार्ग पर होने वाली संभावित दिक्कतों को लेकर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि पहले से की गई तैयारियों के चलते शिव बारात को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराया जाएगा। वहीं आयोजन समिति के सदस्यों ने पुलिस प्रशासन को सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि शिव बारात को परंपरा और मर्यादा के अनुरूप निकाला जाएगा।

पूर्व पालिका अध्यक्ष के परिवार में शोक

बिल्हौर(कानपुर)। आशिक बाग मोहल्ला निवासी सैय्यदा बानो (97) का हृदयगति रुकने से इंतकाल हो गया। वह मकनपुर फेयर कमेटी इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य स्व. कमर हुसैन रिजवी की पत्नी थीं। सोमवार को परिजनों ने उन्हें कस्बे के खानदानी कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया। जनाज़े में परिवारजनों के साथ क्षेत्र के कई लोग मौजूद रहे।

निधन की खबर मिलते ही स्थानीय नागरिक, समाजसेवी व परिचित उनके घर पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त कर परिजनों को ढांढस बंधाया। सैय्यदा बानो, नगर पालिका बिल्हौर के पूर्व अध्यक्ष रहे चौधरी इशरत हुसैन उर्फ प्यारे साहब की भाभी थीं।

पुण्यतिथि पर याद किए गए हिंदुओं के चहेते काला बच्चा

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। हिंदुत्व की रक्षा के लिए संघर्ष करते हुए अपनी जान गंवाने वाले काला बच्चा की 32वीं पुण्यतिथि पूरे सम्मान और भावुक वातावरण में मनाई गई। उत्तरी गांव स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। कार्यक्रम में बिल्हौर विधायक राहुल बच्चा सोनकर ने अपने पिता की शहादत को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन राष्ट्रभक्ति, साहस और संघर्ष की मिसाल है। उन्होंने कहा कि उनके विचार और त्याग आज भी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा हैं।

- उत्तरी गांव भाजपा कार्यालय में दी गई श्रद्धांजलि, भाजपा के कई दिग्गज आए
- विधायक ने मां और भाई के साथ सामाजिक दायित्व निभाते हुए बांटी साड़ियां

इस अवसर पर विधायक ने अपनी माता एवं भाई मोहित सोनकर के साथ जरूरतमंद महिलाओं को साड़ियां वितरित कीं। भाजपा जिलाध्यक्ष उपेंद्र पासवान ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन के दौर में काला बच्चा कानपुर क्षेत्र में हिंदुत्व की मजबूत आवाज थे। उनका बढ़ता जनसमर्थन देश विरोधी ताकतों को रास नहीं आया और वर्ष 1994 में बम हमले के जरिए उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। उनकी शहादत से पूरा क्षेत्र स्तब्ध रह गया था। कार्यकर्ताओं ने बताया कि स्व. काला बच्चा ने वर्ष 1988 में नगर निकाय चुनाव जीतकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी।

श्रद्धांजलि सभा में जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल वरुण, पूर्व जिलाध्यक्ष कौशल किशोर अवस्थी, ब्लॉक प्रमुख शुभम बाजपेयी, शिवांश चंदेल, रवि दीक्षित, रोहित सोनकर, अखिलेश अवस्थी, उदय शंकर मिश्रा, अनुराग शुक्ला, पूर्व उपाध्यक्ष जेपी कटियार, रिंकू कटियार, कुश अग्निहोत्री, अविनाश शुक्ला, प्रधान संघ अध्यक्ष अजीत सिंह, राजकुमार सिंह भदौरिया,महेंद्र सिंह कुशवाहा, प्रभाकर अवस्थी समेत भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

रात का दूध बना मौत का जहर

मथुरा में पूरे परिवार का अंत

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

दूध में जहर मिलाकर आत्महत्या की आशंका, पति-पत्नी व तीन बच्चों की मौत

मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के महावन थाना क्षेत्र के खप्परपुर गांव में मंगलवार सुबह एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत से हड़कंप मच गया। घर के अंदर पति-पत्नी और उनके तीन बच्चों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जांच में रात के दूध में जहरीला पदार्थ मिलाकर सामूहिक आत्महत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने घर को सील कर फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है।

मंगलवार सुबह परिवार के लोग देर तक बाहर नहीं निकले। इस पर पड़ोसियों को संदेह हुआ। घर के भीतर झांकने पर सभी सदस्य अचेत अवस्था में पड़े मिले। सूचना पर महावन थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां मौके पर ही सभी की मौत की पुष्टि की गई। पुलिस की प्रारम्भिक जांच में घर के अंदर दूध के गिलास मिले हैं। किसी प्रकार के जबरन प्रवेश या संघर्ष के निशान नहीं हैं। प्रारंभिक तौर पर जहर सेवन की आशंका जताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा। घटना की खबर मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। घर सील कर साक्ष्य सुरक्षित किए गए। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर जांच-पड़ताल की। जांच के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कारवाई होगी। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आर्थिक दबाव, पारिवारिक तनाव या किसी अन्य कारण से यह कदम उठाया गया या नहीं। घटना के बाद खप्परपुर गांव में शोक और सन्नाटा पसरा है। ग्रामीणों के मुताबिक परिवार शांत स्वभाव का था और किसी विवाद की जानकारी नहीं थी।

- स्थान-खप्परपुर गांव, महावन थाना क्षेत्र, मथुरा
- मृतक-एक ही परिवार के 5 सदस्य
- आशंका-दूध में जहर मिलाकर सेवन
- कार्रवाई-फॉरेंसिक जांच, पोस्टमार्टम
- स्थिति-कारणों की गहन पड़ताल जारी

मान्यवर काशीराम कॉलोनी में बड़ा खेल!

किराए पर मौज, गरीबों के घरों पर कब्जा, अफसर बेअसर

» कब्जाधारियों ने कहा, हमने ये आवास पैसे देकर खरीदे हैं, खाली नहीं करेंगे

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

फर्रुखाबाद। नगर पालिका परिषद के बंधऊ क्षेत्र स्थित मान्यवर काशीराम कॉलोनी में निर्बल एवं असहाय वर्ग के लिए बनाए गए सरकारी आवास अब भ्रष्टाचार और मिलीभगत की खुली मिसाल बन चुके हैं। यहां गरीबों के लिए बने घरों में न तो असली आवंटी रहते हैं और न ही प्रशासन की चेतावनी का कोई असर दिख रहा है।

कॉलोनी में कुल 36 आवासों का निर्माण कराया गया था। जांच में सामने आया कि जिन लोगों के नाम ये आवास आवंटित हैं, वे खुद यहां नहीं रहते, बल्कि किराए पर चढ़ाकर हर महीने पैसा वसूलते रहे। महीने की तय तारीख पर आकर किराया लिया जाता और फिर पूरा महीना नदारद। जांच के बाद 19 आवासों का आवंटन निरस्त कर दिया गया था। इसके बावजूद इन आवासों में आज भी ताले लटक रहे हैं और किसी जरूरतमंद को आवंटन नहीं मिला। शेष 16 आवासों में से 4 आवासों पर अवैध कब्जा बना हुआ है। शिकायत मिलने पर डूडा और नगर पालिका की टीम जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के आदेश पर मौके पर पहुंची और अवैध रूप से रह रहे लोगों को मकान खाली करने को कहा। कार्रवाई के दौरान

इन आवासों पर अवैध कब्जा

आवास संख्या 7- प्रदीप कुमार के नाम आवंटित, किरायेदार का अवैध कब्जा

आवास संख्या 8- स्व. आशा देवी के नाम, राजेश कुमार लंबे समय से कब्जे में आवास संख्या 13 -जयंत सिंह के नाम, बबली पत्नी कमलेश कुमार का अवैध कब्जा

कब्जाधारियों ने न सिर्फ़ आवास खाली करने से इनकार किया, बल्कि यह तक कह दिया कि हमने ये आवास पैसे देकर खरीदे हैं, खाली नहीं करेंगे। प्रशासनिक टीम से तीखी बहस हुई, लेकिन एक भी आवास खाली नहीं कराया जा सका।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन लोगों के नाम आवास किसने और कैसे आवंटित किए? सरकारी आवासों को पैसे लेकर किसने बेचा?। क्या डूडा और नगर पालिका के कुछ कर्मचारी इस खेल में शामिल हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि एक साल पहले ही विभाग द्वारा नोटिस जारी किए जा चुके थे, इसके बावजूद आज तक न तो कब्जा हटा और न ही किसी जिम्मेदार पर ठोस कार्रवाई हुई। डूडा और नगर पालिका विभाग के कर्मचारियों को जांच में लगाया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है क्या सिर्फ जांच होगी या दोषियों पर कार्रवाई भी होगी? गरीबों के हक के घरों पर कब्जा और खुलेआम बिक्री का यह मामला अब प्रशासन की नीयत और सख्ती दोनों की परीक्षा बन गया है।

पिता को 'मृत' दिखाकर जमीन हड़पने की कोशिश

» बेटे ने फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर रुकवाई पेंशन व किसान सम्मान निधि

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

फर्रुखाबाद। जमीन हड़पने की नीयत से एक बेटे ने अपने ही जीवित पिता को कागज़ों में मृत घोषित कर दिया। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर उसने पिता की वर्षों से आ रही वृद्धावस्था पेंशन और किसान सम्मान निधि की राशि रुकवा दी। पीड़ित पिता ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपते हुए अपने बेटे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।रामपुर माझंगांव, विकासखंड कमालगंज निवासी सूबेदार ने जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि उन्हें नियमित रूप से वृद्धावस्था पेंशन और किसान सम्मान निधि की राशि मिलती थी, जो अचानक बंद हो गई। जानकारी करने पर पता चला कि उनके बड़े पुत्र अशोक कुमार शुक्ला ने उन्हें मृत घोषित कर सरकारी रिकॉर्ड में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र लगवा दिया है।पीड़ित का आरोप है कि बेटे ने यह कृत्य उनकी भूमि पर कब्जा करने के उद्देश्य से किया, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ रुक जाए और उन्हें कानूनी रूप से कमजोर किया जा सके। सूबेदार ने मांग की है कि फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी ने पीड़ित को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

भ्रष्टाचार के आगे बिल्हौर रजिस्ट्रार को नहीं दिख रही फर्जी रजिस्ट्री !

» मुंबई में बसे बकोठी गांव के चाचा-ताउ की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री हो गई जिम्मेदार कार्रवाई के बजाय तर्क वितर्क कर रहे हैं

» बिल्हौर तहसील क्षेत्र में नियम कायदों की धज्जियां उडाकर हडपी जा रही जमीनें

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

जिम्मेदारों के बयान.....

-मामले की जानकारी उपनिबंधक बिल्हौर से करके उचित कार्रवाई की जाएगी। नियमों के विपरीत रजिस्ट्री अगर हुई तो उसको निरस्त किया जाएगा।

श्याम सिंह, एआईजी स्टांप

-प्रकरण की जानकारी है, इसमें प्रथम दृष्टया रजिस्ट्री कार्यालय में ही देखा जाना चाहिए कि उसमें डाक्यूमेंट सही यह नहीं, बाकी तो दाखिल खारिज में आपत्ति नहीं आई तो हो गया है लेकिन इसपर नजर है।

संजीव दीक्षित, एसडीएम बिल्हौर

कानपुर। बिल्हौर तहसील के बकोठी गांव में कृषि जमीन जिसके मालिकान मुंबई में सालों पहले चले गए और आजतक नहीं आए। इस बात की तस्दीक स्थानीय ग्रामीण भी करते हैं। भ्रष्टाचार और सांठगांठ करके भतीजे ने अन्य व्यक्ति को खडा करके उनकी कृषि जमीन की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री अपनी पत्नी के नाम करा ली। मामला खुलासा भी हुआ लेकिन अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। प्रकरण में बिल्हौर तहसील के रजिस्ट्रार और कुछ अधिवक्ताओं की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है क्यों कि इस तरह से एक नेक्सेस तहसील से लेकर रजिस्ट्री कार्यालय तक सक्रिय है। सबसे खास बात यह है कि बिना आधार, पैन कार्ड के सत्यापन के ही रजिस्ट्री कर दी गई। अब जब इस मामले में बिल्हौर के रजिस्ट्रार इरशाद से बात की गई तो वह कहते हैं कि आधार कार्ड देखे गए थे लेकिन अगर वह फर्जी थे तो हम कैसे जानें कि फर्जी हैं। ऐसे तो कोई भी किसी जमीन मकान की रजिस्ट्री कर देगा। जब कि रजिस्ट्री के समय विक्रेता-क्रेता का पेन कार्ड, आधार कार्ड और खाते में धनराशि का ट्रांजेक्शन चेक करना प्राथमिक कार्य हैं लेकिन इसकी अनदेखी की गई। उपनिबंधक इरशाद मामले की जांच की बजाय बचाव करते दिखते हैं। इससे उनकी भूमिका भी सवालों से घिर गई है।

स्वराज इंडिया संवाददाता ने जब रजिस्ट्री की पडताल की कई चैकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। विक्रेता कल्याण दत्त के नाम के आगे जो मोबाइल 9936686221 नंबर दर्ज है उसपर कॉल की गई तो फोन रोहित शर्मा नाम के व्यक्ति उठाता है। जब कल्याण दत्त के बारे में पूछा जा रहा है तो बताया कि वह यहां नहीं है, कहा कि उनका मोबाइल बंद है दो तीन में बात करा दूंगा, रिपोर्टर ने 5 दिन बाद फिर फोन किया तो रोहित शर्मा ने टहलाने का प्रयास कर इधर उधर की बातें की। जब उनका मुंबई का पता पूछा गया तो वह भी नहीं बता सका।

वहीं, ग्रामीणों ने बताया कि रोहित, कल्याण दत्त का भतीजा है। उसी ने पूरे खेल का अंजाम दिया है। वहीं, रजिस्ट्री के पृष्ठ संख्या 5 में गवाही के तौर पर भी रोहित का ही नाम दर्ज है। जब कि केता कामिनी, रोहित की पत्नी है। वहीं, एक गवाह में उपेंद्र पुत्र प्रदीप निवासी बकोठी का नाम दर्ज है, जब उसके मोबाइल पर संपर्क किया गया तो उसने बताया कि हमे ज्यादा जानकारी नहीं है, रोहित हमको ले गए थे, पैसे का लेनदेन भी मेरे सामने नहीं हुआ है। गवाह ने अपनी उम्र करीब 32 साल बताई जब कि कल्याण दत्त और नारायन दत्त करीब 40 साल पहले गांव से चले गए थे तो सबसे बडा सवाल यह है कि उसने उनकी शिनाख्त कैसे की जब वह पैदा भी नहीं हुआ था।

दयानंद गर्ल्स पीजी कॉलेज में लगा रोजगार मेला 300 छात्राएं शॉर्टलिस्ट

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। दयानंद गर्ल्स पीजी कॉलेज में मंगलवार को आयोजित रोजगार मेले में 500 से अधिक छात्राओं ने भाग लिया। आयोजन का उद्देश्य छात्राओं को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना रहा।जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशन में आयोजित इस मेले का आयोजन कॉलेज, प्रादेशिक सेवायोजन कार्यालय, आईआईएफए प्लेसमेंट और एएमपी कानपुर के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। विशिष्ट अतिथि श्रीमती अनंता स्वरूप ने कहा कि रोजगार मेला छात्राओं और कंपनियों के बीच सेतु का कार्य करता है और करियर के नए अवसर उपलब्ध कराता है।सहायक सेवायोजन अधिकारी हिमांशु यादव ने छात्राओं को कौशल विकास, नई तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी।कॉलेज की प्राचार्या प्रो. वंदना निगम ने कहा कि महाविद्यालय छात्राओं को करियर के प्रति जागरूक कर रोजगार के बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। रोजगार मेले में एलन हाउस, ब्लिंकिट, एसबीआई लाइफ, श्रीराम फाइनेंस, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सहित 21 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया, जिनमें 300 से अधिक छात्राओं को विभिन्न पदों के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. अलका सिंह ने किया। प्लेसमेंट सेल की इंचार्ज क्षमा त्रिपाठी ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

लैंबॉर्गिनी हादसा: पुलिस का स्टैंड साफ, शिवम मिश्रा ही चला रहा था कार

» वीडियो साक्ष्यों के आधार पर ड्राइवर वाले दावे खारिज, आरोपी पर एफआईआर दर्ज

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। लैंबॉर्गिनी कार हादसे को लेकर पुलिस ने अपना रुख पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि उपलब्ध सीसी टीवी फुटेज और वीडियो साक्ष्यों के आधार पर यह तय हो चुका है कि हादसे के वक्त लैंबॉर्गिनी शिवम मिश्रा ही चला रहा था। ड्राइवर के वाहन चलाने के दावों को पुलिस ने खारिज कर दिया है। मामले में शिवम मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

यह हादसा ग्वालटोली थाना क्षेत्र के वीआईपी रोड पर हुआ, जहां तेज रफ्तार लैंबॉर्गिनी कार ने पहले एक ऑटो और फिर सड़क किनारे खड़े वाहनों को टक्कर मार दी। घटना में कई लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस कमिश्नर ने मीडिया को बताया कि शुरुआती जांच में सामने आए सभी वीडियो और चश्मदीदों के बयान एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून के सामने कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, और मामले में किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी।

इस बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री ने भी घटना को गंभीर बताते हुए कहा है कि दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि लापरवाही या कानून उल्लंघन पाया गया तो पुलिस को पूरी छूट है।

वहीं आरोपी शिवम मिश्रा के पिता और पक्षकारों की ओर से बचाव में यह कहा गया कि कार कोई और चला रहा था,

लेकिन पुलिस का कहना है कि ये दावे जांच में टिक नहीं पाए हैं।

वायरल वीडियो में शिवम मिश्रा को ही कार से बाहर निकलते हुए देखा गया है, जिससे पुलिस के दावे को मजबूती मिली है।

पुलिस ने बताया कि मामले में आईपीसी और मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

आगे की कार्रवाई के तहत आरोपों की जांच, घायलों के बयान और तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया तय की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी।

सरकारी दवा से 100 स्कूली बच्चे बीमार

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

फर्रुखाबाद। कमालगंज ब्लॉक के थाना जहानगंज क्षेत्र स्थित महरुपुर बीजल के जवाहरलाल विद्यालय में सरकारी स्वास्थ्य अभियान के तहत बच्चों को दी गई कीड़ामार दवा ने बड़ा हादसा खड़ा कर दिया। एल्बेंडाजोल दवा खाने के बाद करीब एक सैकड़ा बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जबकि एक बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है।

घटना मंगलवार की है, जब विद्यालय में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अंतर्गत बच्चों को दवा खिलाई गई। दवा सेवन के कुछ ही देर बाद बच्चों को पेट दर्द, उल्टी, चक्कर और घबराहट की शिकायत होने लगी। देखते ही देखते कई बच्चे बेहोश हो गए, जिससे स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई।

स्थिति गंभीर होने पर बच्चों को आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां से 40 बच्चों को लोहिया अस्पताल

रेफर किया गया। वर्तमान में 12 से अधिक बच्चे लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं। चिकित्सकों के अनुसार एक बच्चे की हालत मरणासन बनी हुई है, जबकि अन्य बच्चों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है।घटना की सूचना मिलते ही आक्रोशित अभिभावक स्कूल और अस्पताल पहुंच गए। लापरवाही के आरोप में दवा खिलाने वाले दो कर्मचारियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

प्रशासन की प्रारंभिक जांच में यह बिंदु सामने आ रहा है कि बच्चों को दवा खाली पेट दी गई या निर्धारित मानकों का पालन नहीं हुआ। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है।

खबर: एक नजर में

- सरकारी अभियान के तहत एल्बेंडाजोल दवा खिलाने के बाद स्कूल में बड़ा हादसा
- करीब 100 बच्चे बीमार, एक की हालत मरणासन्न
- थाना जहानगंज क्षेत्र के जवाहरलाल विद्यालय, महरुपुर बीजल की घटना
- दवा खाते ही बच्चों को पेट दर्द, उल्टी, चक्कर, घबराहट
- स्कूल परिसर में मची अफरा-तफरी, पढ़ाई तुरंत रोकी गई
- 20 से अधिक बच्चे तुरंत ष्ट॥ष्ट ले जाए गए
- 40 बच्चों को लोहिया अस्पताल रेफर किया गया
- 12 से ज्यादा बच्चे अभी भी भर्ती, डॉक्टरों की निगरानी में
- लापरवाही के आरोप में दवा खिलाने वाले दो कर्मचारी हिरासत में
- अभिभावकों में आक्रोश, स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ हंगामा
- जांच में खाली पेट दवा देने और डोज चूक की आशंका
- स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने जांच के आदेश दिए

20 लाख की वसूली में दारोगा गैंग बेनकाब

» कारोबारी को अगवा कर जेल भेजने की धमकी, लोकेशन-फुटेज से खुला खेल

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

मेरठ। यूपी के मेरठ में खाकी की साख को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। लोहियानगर थाने में तैनात दो दारोगाओं पर एक धागा कारोबारी के अपहरण, अवैध हिरासत और 20 लाख रुपये की जबरन वसूली का गंभीर आरोप लगा है। गोपनीय जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए हैं। मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है, जबकि दोनों आरोपी दारोगा फरार बताए जा रहे हैं।पीड़ित कारोबारी लिसाड़ी गेट क्षेत्र का रहने वाला है और धागा व्यापार व इंपोर्ट-एक्सपोर्ट से जुड़ा है। मेरठ और दुबई में उसकी संपत्तियां हैं। हाल में जमीन बिक्री से मिली बड़ी रकम की जानकारी मिलने पर एक कथित मुखबिर ने दोनों दारोगाओं से मिलकर वसूली की साजिश रची। आरोप है कि 2023 बैच के दोनों दारोगाओं ने कारोबारी को अगवा कर सोना तस्करी के फर्जी केस में जेल भेजने की धमकी दी और 20 लाख रुपये वसूल लिए। घटना के करीब सात दिन बाद दोबारा फोन कर 10 लाख रुपये और मांगे गए, जिससे घबराकर कारोबारी ने एसएसपी और एसपी सिटी से शिकायत की।

अधिकारियों के निर्देश पर कराई गई गोपनीय जांच में मोबाइल लोकेशन और समय का मिलान हुआ। वसूली वाले दिन कारोबारी और दोनों दारोगाओं की लोकेशन एक ही स्थान पर पाई गई। साथ ही सीसीटीवी व वीडियो

फुटेज में कारोबारी को कार में बंधक बनाकर घुमाते हुए देखा गया। पूछताछ के लिए बुलाने पर 15 लाख रुपये बरामद कराए गए, जबकि शेष 5 लाख देने का भरोसा देकर दोनों दारोगा मौके से फरार हो गए। पुलिस ने अगवा, अवैध हिरासत, जबरन वसूली, धमकी और भ्रष्टाचार समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज करने की तैयारी पूरी कर ली है। अधिकारियों के मुताबिक, गिरफ्तारी के बाद निलंबन और बर्खास्तगी की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।

डेरापुर-गलुवापुर-खजुर्रा-नोनारी सड़क की बदहाली से ग्रामीणों में रोष

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। जिले के डेरापुरङ्गगलुवापुर से खजुर्रा होते हुए नोनारी तक जाने वाली ग्रामीण सड़क की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। सड़क की बदहाली के कारण स्थानीय लोगों को रोज़ाना आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीणों के अनुसार इस मार्ग पर कई स्थानों पर सड़क ढहने की स्थिति में है। जगह-जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं और कई हिस्सों में सड़क पूरी तरह कच्चे रास्ते में तब्दील हो चुकी है। इससे वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।सड़क की खराब स्थिति से सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों, पैदल राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को हो रही है। बरसात के मौसम में गड्ढों में पानी भर जाने से वाहन फँस जाते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि बारिश के दौरान हालात और भी खराब हो जाते हैं। बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को इस रास्ते से निकलना मुश्किल हो जाता है। इससे ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है।इस संबंध में युवा समाजसेवी आशुतोष त्रिपाठी ने डेरापुर तहसील सभागार में आयोजित जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी के समक्ष सड़क की तत्काल मरम्मत कराए जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो किसी बड़े हादसे से इंकार नहीं किया जा सकता।

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि सड़क की जल्द मरम्मत कराई जाए, जिससे क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके।

जल्लापुर गांव में तेंदुआ दिखा, लोग दहशत में

राहगीरों ने फोटो-वीडियो बनाकर दी वन विभाग को सूचना

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। राजपुर ब्लॉक के गांवों में इन दिनों तेंदुए की आवाजाही से लोगों में डर बना हुआ है। पहले गुबार और बिजहरा गांव के पास तेंदुआ दिखा था, अब जल्लापुरङ्गसिकंदरा गांव की बस्ती में भी तेंदुआ नजर आया है। इससे गांव के लोग सहमे हुए हैं।

ग्रामीणों के अनुसार कुछ दिन पहले सट्टी थाना क्षेत्र के दिबैर गांव के रास्ते पर झाड़ियों में तेंदुआ बैठा देखा गया था। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने उसका फोटो और वीडियो बनाकर वन विभाग को जानकारी दी थी। इसके बाद तेंदुआ गुबारङ्गपिचौरा के जंगल से गांव की तरफ आता दिखा। तेंदुए के डर से कई किसानों ने खेतों में जाना बंद कर दिया। गुरुवार को बिजहरा गांव के खेतों के पास भी तेंदुआ दिखाई दिया। बीती रात जल्लापुरङ्गसिकंदरा गांव की आबादी में तेंदुआ घूमता हुआ नजर आया। तेंदुआ देखते ही गांव वालों ने शोर मचाया और एक-दूसरे को सावधान किया। सोमवार सुबह इसकी सूचना वन विभाग को दी गई।

वन विभाग की टीम लगी, पकड़ने की तैयारी

भोगनीपुर के वन रेंजर स्वामी दीन ने बताया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम गांव में लगाई गई है। कानपुर चिड़ियाघर से विशेषज्ञ टीम बुलाने के लिए डीएफओ को पत्र लिखा गया है। तेंदुए की तलाश लगातार की जा रही है।

खबर: एक नजर में

- राजपुर ब्लॉक के कई गांवों में तेंदुआ लगातार देखा जा रहा
- पहले गुबार और बिजहरा, अब जल्लापुरङ्गसिकंदरा गांव में तेंदुआ नजर आया
- सोमवार रात गांव की बस्ती में घूमता दिखा तेंदुआ
- तेंदुआ देखते ही ग्रामीणों ने शोर मचाकर एक-दूसरे को किया सतर्क
- डर के कारण कई किसानों ने खेतों में जाना किया बंद
- गांव वालों ने तेंदुआ पकड़ने के लिए जाल लगाने की मांग की
- वन विभाग की टीम मौके पर, सर्च ऑपरेशन जारी
- कानपुर चिड़ियाघर से विशेषज्ञ टीम बुलाने की तैयारी

स्वराज इंडिया
स्वराज इंडिया | अयोध्या | 11
गरीबों पर वार, वीआईपी कार्ट को संरक्षण!
सीधा-सीधा जनविरोधी फैसला

महापौर की पहल से ई-रिक्शा चालकों का आंदोलन खत्म

अयोध्या में बहाल हुई परिवहन व्यवस्था, श्रद्धालुओं और नागरिकों को मिली राहत

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या धाम। अयोध्या में बीते कई दिनों से चल रहा ई-रिक्शा चालकों का आंदोलन सोमवार को समाप्त हो गया। नगर निगम के महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी के प्रभावी हस्तक्षेप और आश्वासन के बाद ई-रिक्शा यूनियन ने हड़ताल वापस लेने की घोषणा कर दी।प्रमोद वन मोहल्ले में कृष्णा फाउंडेशन और अयोध्या जी ई-रिक्शा कल्याण सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में यह आंदोलन चालकों की रोज़ी-रोटी, रूट निर्धारण और प्रशासनिक अड़चनों से जुड़ी मांगों को लेकर चल रहा था। हड़ताल के कारण शहर की परिवहन व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो गई थी, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करते हुए वार्ता कराई। सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई बातचीत के बाद कुछ प्रमुख मांगों पर सहमति बनी, जबकि शेष मांगों पर आगे विचार करने का आश्वासन दिया गया।

ई-रिक्शा यूनियन के संस्थापक माधव मुकुंद त्रिपाठी ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा करते हुए बताया कि प्रशासन द्वारा फिलहाल कुछ अहम मांगों को स्वीकार किया गया है।

उन्होंने कहा कि सीओ स्तर से कुछ क्षेत्रों तक ई-रिक्शा संचालन की अनुमति दिए जाने पर सहमति बनी है, जिसके बाद पुनः संचालन शुरू कर दिया गया है।

हड़ताल समाप्त होने के बाद अयोध्या की परिवहन व्यवस्था के फिर से पटरी पर लौटने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे स्थानीय नागरिकों के साथ-साथ दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को भी बड़ी राहत मिली है।

छात्रों की खेल प्रतियोगिता में शिक्षकों का धमाल

» सम्मान की होड़ में फंसा मंच, महापौर ने संभाली कमान

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। खेल प्रतियोगिता तो छात्रों की थी, लेकिन असली मुकाबला मंच पर शिक्षकों के बीच देखने को मिला। सम्मान पाने की होड़ में अध्यापकों के बीच ऐसी तू-तू मैं-मैं हुई कि पूरा कार्यक्रम कुछ देर के लिए अव्यवस्था का शिकार हो गया। सम्मान समारोह के दौरान मंच पर पहले चढ़ने और नाम पुकारे जाने को लेकर शिक्षकों में आपसी तालमेल नजर नहीं आया।

स्थिति यहां तक पहुंच गई कि मंच पर मौजूद मुख्य अतिथि महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी भी कुछ देर के लिए भौचक रह गए।मामले को बिगड़ता देख महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने हस्तक्षेप करते हुए सभी शिक्षकों को समझाया-बुझाया और शांत कराया। इसके बाद बारी-बारी से शिक्षकों को मंच पर बुलाकर सम्मान कार्यक्रम पूरा कराया गया।

फिलहाल स्पोर्ट्स स्टेडियम में बेसिक शिक्षा विभाग का खेल समारोह चल रहा है, जिसमें ब्लॉक स्तर के छात्र-छात्राएं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद जिला और मंडल स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। कार्यक्रम में जहां एक ओर बच्चों की मेहनत और खेल भावना सराहनीय रही, वहीं शिक्षकों की आपसी खींचतान चर्चा का विषय बनी रही।

लोकप्रिया हॉस्पिटल ने रोका विकास, अफसरों ने बेचा सिस्टम

मुख्यमंत्री से गुहार

स्वराज इंडिया Xक्लूसिव

महंत सन्त दास उर्फ राजेश सिंह मानव की शिकायत से खुला सड़क-नाला घोटाले का पूरा खेल

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। मोदहा चौराहा स्थित लोकप्रिया हॉस्पिटल को लेकर सड़क चौड़ीकरण और नाला निर्माण में हुई कथित अनियमितताओं का मामला अब सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। सामाजिक कार्यकर्ता राजेश सिंह मानव द्वारा भेजी गई शिकायत में सेतु निगम और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत के अनुसार, अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अस्पताल प्रबंधन को अवैध लाभ पहुंचाया और जनसुरक्षा से खिलवाड़ किया।

शिकायत में उल्लेख किया गया है कि मोदहा चौराहा क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण की योजना के तहत लोकप्रिया हॉस्पिटल बाधक था। नियमों के अनुसार पूरे बाधक हिस्से को हटाया जाना था, लेकिन कथित तौर पर अधिकारियों ने दबाव और प्रभाव में आकर केवल आंशिक अधिग्रहण किया। इसके चलते सड़क की दिशा को जबरन मोड़ दिया गया, जिससे पुल से उतरते समय वाहनों को अचानक तीखा मोड़ लेना पड़ता है। इससे दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। शिकायत में नाला निर्माण को भी सवालों के घेरे में रखा है। कहा गया कि मानक चौड़ाई के बजाय संकरी नाली का निर्माण किया गया, जिससे जलनिकासी बाधित होती है और सड़क पर जलभराव की स्थिति बनती है।

शिकायत में सेतु निगम के अधिकारियों और अभियंताओं पर लोकप्रिया हॉस्पिटल के स्वामी के साथ सांठगांठ का आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि कथित रूप से अनुचित लाभ लेकर नियमों को दरकिनार किया गया। शिकायत के अनुसार, सड़क चौड़ीकरण के लिए अस्पताल का केवल एक हिस्सा ही अधिग्रहित किया गया। मुख्य भवन को छोड़ देने के कारण सड़क की चौड़ाई असंतुलित हो गई है। इस असंतुलन के चलते भारी वाहन, एम्बुलेंस और बसों को मोड़ काटने में परेशानी होती है।

मुख्यमंत्री से की गई प्रमुख मांगें

राजेश सिंह मानव ने अपनी शिकायत में मुख्यमंत्री से उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई, अवैध हिस्से का ध्वस्तीकरण सड़क और नाले का मानक के अनुसार पुनर्निर्माण की मांग की है। शिकायत की प्रतिलिपि जिलाधिकारी अयोध्या, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग और सेतु निगम उत्तर प्रदेश को भी भेजी गई है, ताकि मामले पर तत्काल संज्ञान लिया जा सके।

मेडिकल कॉलेज कर्मी पर महिला से शोषण का आरोप

» कोतवाली पुलिस ने नहीं लिया एक्शन, अब एसएसपी से शिकायत

अयोध्या। अयोध्या के मेडिकल कॉलेज में नौकरी दिलाने के नाम पर एक महिला से लाखों रुपये ठगने, अश्लील हरकत करने और आपत्तिजनक फोटो के जरिए ब्लैकमेल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता ने पूरे प्रकरण की शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव ग्रोवर से कर न्याय की गुहार लगाई है।पीड़िता के अनुसार, उसने वार्ड बॉय पद के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। आवेदन की स्थिति जानने के लिए जब वह मेडिकल कॉलेज पहुंची, तो वहां लैब में तैनात एक कर्मचारी ने नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। आरोप है कि आरोपी ने पहले डेढ़ लाख रुपये ऐंठ लिए। इसके बाद उसे सुनसान कमरे में बुलाया, जहां उसके साथ अश्लील हरकत की और चोरी-छिपे आपत्तिजनक फोटो खींच ली।पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने फोटो वायरल करने की धमकी देकर 75 हजार रुपये और वसूल लिए गए, लेकिन इसके बावजूद आरोपी ने फोटो डिलीट नहीं की। इसके बाद आरोपी नौकरी दिलाने के नाम पर आर्थिक व मानसिक शोषण करता रहा। पीड़िता ने पहले कोतवाली अयोध्या में तहरीर दी, लेकिन कार्रवाई न होने पर एसएसपी से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी। एसएसपी ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।पीड़िता की अधिवक्ता श्वेता राज सिंह ने कहा कि यह मामला महज आर्थिक ठगी तक सीमित नहीं है, बल्कि महिला की गरिमा, सम्मान और सुरक्षा से जुड़ा गंभीर अपराध है। उन्होंने कहा कि आरोपी ने सरकारी संस्थान में तैनात होने का फायदा उठाकर महिला को फंसाया और उसका शोषण किया। इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

अधिवक्ता के साथ पीड़िता

नए मेडिकल कॉलेजों से बदली यूपी की सेहत की तस्वीर

डॉक्टरों की फौज बढ़ी, ग्रामीण इलाकों तक पहुंची इलाज की सुविधा

» 81 मेडिकल कॉलेज, 2 करोड़ से ज्यादा मरीजों का इलाज, टेली मेडिसिन से घर बैठे परामर्श

» आर्थिक सर्वेक्षण में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का दमदार खाका

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बीते नौ वर्षों में बड़ा परिवर्तन दर्ज किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान वर्ष 2025-26 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सदन के पटल पर रखते हुए स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में हुई ऐतिहासिक प्रगति को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाबद्ध नीतियों और निरंतर निवेश का असर अब प्रदेश की जमीनी हकीकत में साफ दिखाई दे रहा है।

वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 तक प्रदेश में कुल 36 मेडिकल कॉलेज संचालित थे, जबकि वर्ष 2025 के अंत तक इनकी संख्या बढ़कर 81 हो चुकी है। इनमें 45 राजकीय और 36 निजी मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। मेडिकल कॉलेजों की इस अभूतपूर्व वृद्धि से न केवल प्रदेश में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ी है, बल्कि चिकित्सा शिक्षा के नए अवसर भी तेजी से सृजित हुए हैं।

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मिली नई रफ्तार

ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक इलाज पहुंचाने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। वर्तमान में प्रदेश के 54 जनपदों में 170 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स संचालित हैं, जिनके माध्यम से अब तक 2.05 करोड़ मरीजों का उपचार किया जा चुका है। यह सेवा उन क्षेत्रों में जीवनरेखा साबित हो रही है, जहां अस्पतालों तक पहुंच अब भी चुनौती है।

चिकित्सा शिक्षा में एकरूपता

मेडिकल और डेंटल शिक्षा की गुणवत्ता और पाठ्यक्रमों में समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अटल बिहारी वाजपेयी राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिससे चिकित्सा शिक्षा प्रणाली को एक संगठित दिशा मिली है।

डिजिटल हेल्थ की ओर मजबूत कदम

आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देते हुए प्रदेश में टेली मेडिसिन सेवाओं का भी व्यापक विस्तार किया गया है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप 11 मई 2021 से ई-संजीवनी टेली परामर्श सेवा शुरू की गई। वर्तमान में यह सेवा प्रदेश के 26 मेडिकल कॉलेजों में संचालित है, जिसके माध्यम से अब तक 22.53 लाख से अधिक ओपीडी परामर्श दिए जा चुके हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों के विस्तार, मोबाइल मेडिकल यूनिट और टेली मेडिसिन जैसी पहलों से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को स्थायी मजबूती मिली है और आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा।

शिकायतों के निस्तारण में औरैया पुलिस फिर नंबर वन!

» समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) के अन्तर्गत जनशिकायतों के निस्तारण में प्रदेश रैंकिंग में औरैया पुलिस को मिला लगातार दूसरी बार प्रथम स्थान

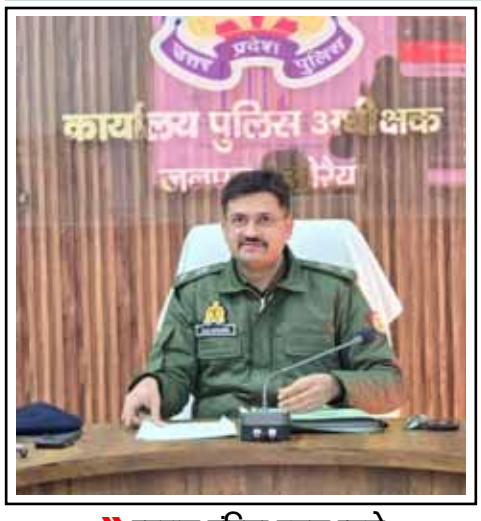

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

औरैया। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की मंशा के अनुरूप जनशिकायतों के समयबद्ध,विधिक एवं उच्च गुणवत्ता के साथ निस्तारण हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती के कुशल निर्देशन में समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में माह जनवरी -2026 की प्रदेश रैंकिंग में जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का मुख्यमंत्री कार्यालय से मूल्यांकन में प्रदेश के सभी 75 जिलों में जनपद औरैया को लगातार दूसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।शासन की मंशा के अनुरूप शिकायतकर्ता को न्याय दिलाना ही प्राथमिकता रही,और यह लक्ष्य पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती की सक्षम निगरानी व सख्त अनुशासन से ही संभव हो सका।(पिछले माह में भी प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था।) इसके साथ ही थाना रैंकिंग में जनपद के 10 थानों को शत-प्रतिशत कार्यवाही के लिये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।औरैया पुलिस द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन,ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों,समाधान दिवस,उच्चाधिकारीगण आदि पटलों से प्राप्त शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया गया।इस उपलब्धि के लिए पुलिस अभिषेक भारती ने आईजीआरएस सेल से जुड़े सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगणों की कर्तव्यनिष्ठा की प्रशंसा की है तथा उन्हें पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया गया है।भविष्य में भी इसी प्रकार जनसेवा हेतु तत्पर रहने के निर्देश दिए हैं।वही पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने बताया कि यह उपलब्धि टीम औरैया के समर्पण और संवेदनशील कार्यशैली का परिणाम है।हमारा उद्देश्य मात्र निस्तारण नहीं,गुणवत्तापूर्ण समाधान देना है,ताकि जनमानस में पुलिस के प्रति विश्वास और मजबूत से स्थापित हो..!!

प्रथम रैंक प्राप्त थानों के नाम

01.अछल्दा 02.बिधूना, 03. अजीतमल, 04. फफूँद, 05. दिबियापुर, 06. एरवाकटरा 07.अयाना 08. सहायल 09. महिला थाना 10.सहार

शिकायतों के निस्तारण में इटावा का जलवा बरकरार

इटावा के 21 थानों में से 20 नंबर वन है

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

इटावा। एक समय था जब जनता को छोटी-छोटी शिकायतों के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे और पीड़ाएं महीनों तक अनसुनी रह जाती थीं, लेकिन जब नेतृत्व संवेदनशील, दृष्टि साफ और निगरानी सतत हो, तो व्यवस्था की तस्वीर बदल जाती है। इटावा जनपद में यही सकारात्मक बदलाव आज साफ दिखाई दे रहा है।जनपद इटावा ने प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जनसुनवाई समाधान प्रणाली (आईजीआरएस) पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण में एक बार फिर प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल कर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। शासन की ओर से जारी जनवरी माह की रैंकिंग में इटावा ने उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि प्राप्त की।यह सफलता जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश श्रीवास्तव की दूरदर्शी सोच, सशक्त रणनीति, कड़ी निगरानी और मानवीय दृष्टिकोण का प्रत्यक्ष परिणाम मानी जा रही है। उनके नेतृत्व में पुलिस व्यवस्था केवल कार्रवाई तक सीमित न रहकर समाधान, संतुष्टि और भरोसे की मिसाल बनकर उभरी है।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक शिकायत को पीड़ा और हर प्रार्थना पत्र को न्याय की उम्मीद मानते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए, जिसका असर थानों के कार्यप्रणाली में साफ नजर आया। भरथना, कोतवाली, सहसों, ऊसराहार, जसवंतनगर, बढ़पुरा, सफाई, इकदिल, बसरेहर, बकेवर, भरेह, पछायगांव, बलराई, लवेदी, सिविल लाइन, महिला थाना, फ्रेंड्स कॉलोनी, वैदपुरा, चौबिया और चकरनगर थानों ने अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य कर इस उपलब्धि में अहम भूमिका निभाई।

नए वर्ष की शुरुआत में ही इटावा पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आधुनिक पुलिसिंग का अर्थ केवल कानून कार्रवाई नहीं, बल्कि समस्याओं का त्वरित समाधान और जनता का विश्वास जीतना है।

इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा आईजीआरएस से जुड़े सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया।

एपस्टीन फाइल्स से यूरोप में सियासी जलजला

नाम आने के दावों से सरकारें घिरीं, इस्तीफे और जांच की मांग तेज

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। अमेरिका के कुख्यात यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़े करीब 30 लाख से अधिक दस्तावेज सार्वजनिक होने के बाद यूरोप की राजनीति में जबरदस्त उथल-पुथल मच गई है। दस्तावेजों में प्रभावशाली राजनेताओं, पूर्व अधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय हस्तियों के नाम संपर्क सूची या संवाद रिकॉर्ड में होने के दावों ने कई सरकारों को कठघरे में खड़ा कर दिया है। विपक्षी दलों ने पारदर्शी जांच, नैतिक जवाबदेही और इस्तीफों की मांग तेज कर दी है।

ब्रिटेन में पूर्व राजनयिक पीटर मैंडेलसन का नाम सामने आने के दावों के बाद राजनीतिक विवाद गहरा गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की सरकार पर विपक्ष ने नैतिक जिम्मेदारी तय करने का दबाव बनाया है। इसी बीच प्रधानमंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ के इस्तीफे ने संकट को और बढ़ा दिया है।

शाही परिवार से जुड़े प्रिंस एंड्रयू पहले से ही एपस्टीन प्रकरण को लेकर विवादों में रहे हैं और फाइल्स सामने आने के बाद यह मामला फिर सुर्खियों में आ गया है। इसके अलावा नॉर्वे, स्वीडन और स्लोवाकिया सहित कई देशों में पूर्व व वर्तमान अधिकारियों के नाम सामने आने के दावे किए गए हैं।

- ब्रिटेन से नॉर्डिक देशों तक दबाव बढ़ा, विपक्ष ने घेरा
- दस्तावेजों में संपर्क के दावे, दोष सिद्ध नहीं फिर भी सियासत में उबाल

अमेरिका में भी बहस तेज

अमेरिका में एपस्टीन नेटवर्क को लेकर राजनीतिक बहस फिर तेज हो गई है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बिल क्लिंटन के नाम पहले भी चर्चाओं में रहे हैं। हालांकि सभी पक्ष इस बात पर जोर दे रहे हैं कि दस्तावेजों में नाम आना और कानूनी दोष सिद्ध होना अलग बातें हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इन खुलासों ने वैश्विक स्तर पर सत्ता, प्रभाव और जवाबदेही को लेकर नई बहस छेड़ दी है। आने वाले दिनों में यूरोप ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इसकी गूंज और तेज हो सकती है। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि दस्तावेजों में नाम आना अपराध सिद्ध होने के बराबर नहीं है। जांच प्रक्रिया जारी है।

- **स्वीडन:** एक पूर्व अंतरराष्ट्रीय अधिकारी ने पद छोड़ा
- **स्लोवाकिया:** एक सुरक्षा सलाहकार का इस्तीफा
- **पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया:** फाइल्स की जांच के लिए विशेष टीमें गठित
- पोलैंड के प्रधानमंत्री ने संभावित पीड़ितों और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की गहन जांच का ऐलान किया है।

यह भी जानना जरूरी

- सार्वजनिक दस्तावेज: 30 लाख+
- असर: ब्रिटेन, नॉर्डिक, पूर्वी यूरोप
- स्थिति: नाम आने का दावा, दोष सिद्ध नहीं
- मांग: स्वतंत्र व पारदर्शी जांच

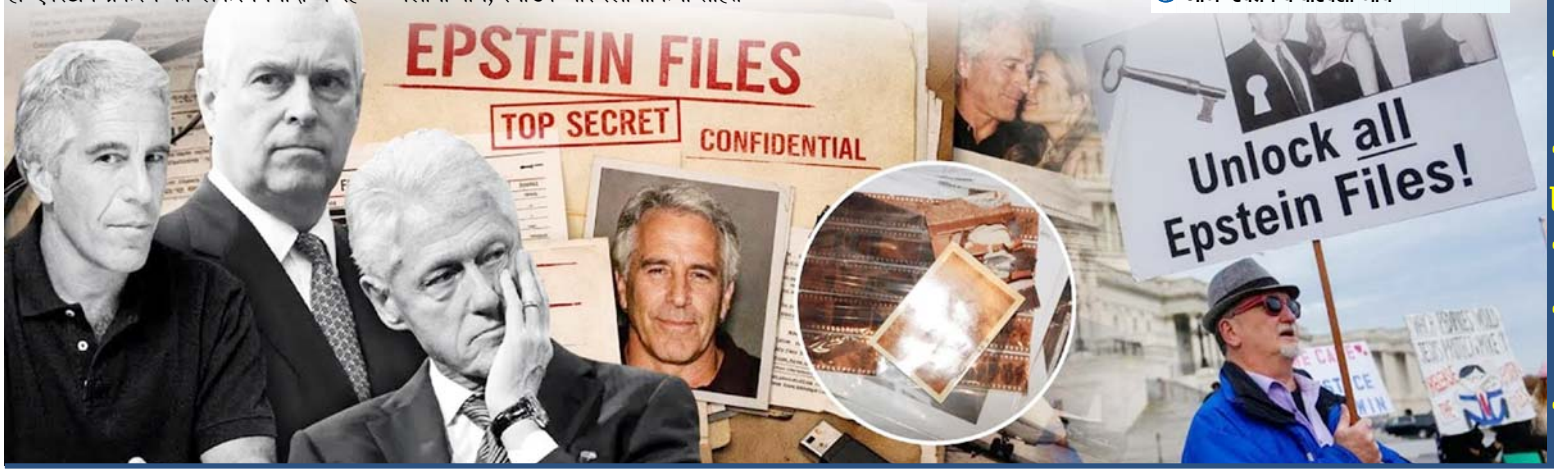

टाइमलाइन

2008
- जेफ्री एपस्टीन पहली बार यौन शोषण के मामलों में दोषी करार
- सीमित सजा के बाद मामला वैश्विक आलोचना में आया

2019 (जुलाई)
- न्यूयॉर्क में एपस्टीन की गिरफ्तारी
- नाबालिगों की तस्करी और यौन शोषण के गंभीर आरोप

2019 (अगस्त)
- जेल में एपस्टीन की संदिग्ध मौत
- मौत को लेकर साजिश और नेटवर्क पर सवाल

2020-2023
- अमेरिकी अदालतों में एपस्टीन नेटवर्क से जुड़े दस्तावेज सीलबंद
- पीड़ितों और मानवाधिकार संगठनों की सार्वजनिक करने की मांग

जनवरी 2026
- अमेरिकी अदालत के आदेश पर 30 लाख से अधिक दस्तावेज सार्वजनिक
- संपर्क सूची, ईमेल, यात्रा रिकॉर्ड सामने आने के दावे

फरवरी 2026
- ब्रिटेन में राजनीतिक विवाद तेज
- प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी का इस्तीफा
- विपक्ष ने स्वतंत्र जांच की मांग की

फरवरी 2026 (वर्तमान)
- नॉर्वे, स्वीडन, स्लोवाकिया में इस्तीफे
- पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया ने विशेष जांच टीमें गठित कीं
- यूरोप में राजनीतिक भूचाल, जवाबदेही पर बहस तेज

'नकली लचीलेपन' के अंत और अधिकारों की बहाली की मांग

नई नीति के विरोध में शहरी कंपनी के कर्मचारी हड़ताल पर

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। शहरी कंपनी की नई नीतियों के विरोध में उसके कर्मचारियों का स्व-संगठित समूह 'गिग वर्कर्स शक्ति ग्रुप' मंगलवार को जंतर-मंतर पर हड़ताल पर रहा। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चले इस प्रदर्शन में कर्मचारियों ने कंपनी द्वारा लागू की गई नई नीति को वापस लेने और 'लचीलेपन' के नाम पर बढ़ाई गई निगरानी व दंडात्मक कार्रवाइयों को खत्म करने की जोरदार मांग की।

गिग वर्कर्स शक्ति ग्रुप के अनुसार, पिछले पांच महीनों से देशभर में लगातार विरोध के बावजूद प्रबंधन ने कर्मचारियों की समस्याओं पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। नई नीति के तहत कामकाज पर सख्त नियंत्रण, आईडी ब्लॉकिंग का खतरा और एकतरफा नियम लागू किए गए हैं, जिससे कर्मचारियों–खासतौर पर महिलाओं–पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है।

प्रदर्शन के दौरान समूह की नेता रोशन ने कहा, "हम महिलाएं और श्रमिक अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरे हैं। कंपनी ने शामिल होते समय परिवार की देखभाल के अनुकूल लचीले काम का वादा किया था, लेकिन अब हमें डिजिटल बंधुआ मजदूरी की व्यवस्था में धकेला जा रहा है। नियमों का पालन न करने पर आईडी ब्लॉक कर दी जाती है।"

उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी महिलाओं की अवैतनिक देखभाल और घरेलू जिम्मेदारियों को मजबूरी बनाकर 'लचीलेपन' का दिखावा करती है, जबकि व्यवहार में सख्त और दमनकारी नीतियां थोप दी गई हैं। समूह के एक अन्य नेता योगेश ने कहा, "हमसे प्रशिक्षण के नाम पर 60 हजार रुपये तक वसूले गए। इसके बाद नए प्रशिक्षण और उत्पादों के लिए भी लगातार भुगतान कराना पड़ता है। अब जब नियम पूरी तरह बदल दिए गए और सभी वादे खत्म कर दिए गए, तो क्या हमारा पैसा वापस मिलेगा? यह खुला घोटाला है।"

गिग वर्कर्स शक्ति ग्रुप की प्रमुख मांगें

- **आईडी ब्लॉकिंग नीति:** 3-4 वर्षों से कार्यरत दीर्घकालिक साझेदारों की आईडी बिना ठोस और वैध कारण के ब्लॉक न की जाए।
- **कमीशन प्रणाली:** कमीशन घटाकर अधिकतम 20 प्रतिशत तक सीमित किया जाए।
- **कैंसिलेशन नीति:** डबल (1 के बदले 2) कैंसिलेशन नीति तत्काल समाप्त की जाए।
- **हब व लोकेशन:** हब साझेदार के वर्तमान स्थान से 7-8 किलोमीटर के भीतर हो, ताकि सुरक्षा और यात्रा की समस्याएं न हों।
- **पीक आवर सिस्टम:** कर्मचारियों को हर शाम उपलब्ध रहने के लिए मजबूर करने वाला सिस्टम हटाया जाए।
- **टूल व ऑडिट नीति:** उपकरणों पर न्यूनतम वारंटी दी जाए और टूल ऑडिट साल में अधिकतम एक बार किए जाएं।
- **45-मिनट सेवा नियम:** 45 मिनट में सेवा पूरा करने की बाध्यता हटाई जाए।
- **बंडल बुकिंग:** बंडल बुकिंग सिस्टम बंद किया जाए।
- **एआई कॉलिंग:** एआई कॉलिंग समाप्त कर मानव सहायक एजेंट से सीधे संपर्क का अधिकार दिया जाए।
- **रेटिंग सिस्टम:** 100 ग्राहकों के बाद रेटिंग बढ़ने की शर्त कम की जाए।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **सपना देवी** द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादक: अनूप कुमार** **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 ❍ **Email:** swarajindia2023@gmail.com ❍ Mob: 7800009853, ❍ **Website:** www.swarajindianews.com ❍ (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे) **प्रधान संपादक: पुरुषोत्तम द्विवेदी**

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com